वर्तमान अरब संकट और उभरते परिदृश्य

डा. फजुर रहमान सिद्दीकी

वर्तमान अरब संकट और उभरते परिदृश्य

प्रथम प्रकाशन, 2017

प्रतिलिप्यधिकार © विश्व मामलों की भारतीय परिषद्.

आईएसबीएन : 978-93-83445-33-2

सभी अधिकार सुरक्षित हैं। इस प्रकाशन का कोई भी भाग कॉपीराइट स्वामी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से , इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग, या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में तथ्यों और विचारों की जिम्मेदारी विशेष रूप से लेखक के साथ है और उसकी व्याख्या , विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्,
बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110 001, भारत
दूरभाष. : +91-11-23317242, फैक्स: +91-11-23322710
www.icwa.in

मुद्रण:
एल्फा ग्राफ़िक्स
6A/1, गंगा चैम्बर्स, डबल्यू.ई.ए., करोल बाग. नई दिल्ली -110005
दूरभाष : 9312430311
ई-मेल : tarunberi2000@gmail.com

विषय-वस्तु

सार

प्रस्तावना

निरंतर उथल-पुथल के छह वर्ष और इसे भू-रणनीतिक परिणाम

घटनाक्रम

वर्तमान जटिलताएं और उभरते परिदृश्य

अरब विश्व में संभावित भावी परिदृश्य

समग्र अरब परिदृश्य

निष्कर्ष

वर्तमान अरब संकट और उभरते परिदृश्य

"कल्पना ज्ञान की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज्ञान उन सभी बातों तक सीमित रहता है जो हम जानते हैं और समझते हैं, जबकि कल्पना में संपूर्ण विश्व समाहित होता है, तथा वहां जो कुछ भी विद्यमान है, उसे कभी तो जाना और समझा जाएगा ही।"

- एल्बर्ट आइंस्टाइन

सार

भविष्य की कल्पना करना सदैव ही एक कठिन कार्य रहा है, फिर भी विश्लेषकों और शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाने का प्रयास किया है, विशेष रूप से किसी संदर्भ-विशेष के भीतर घटने वाली किस प्रमुख उत्पाती घटना के आधार पर। किसी घटना-विशेष में शामिल प्रकृति और गतिशीलता की सूचना कतिपय प्रवृत्तियों द्वारा दी जाती है, जो भविष्य के संभावित विवक्षाओं और पूर्वानुमानों को समझने के कार्य को सुकर बनाती है। ऐसी ही बात आज के अरब विश्व के मामले में भी सत्य है, जहां कुछ संभावनाओं की परिकल्पना करना आसान कार्य नहीं है। अरब विश्व में वर्तमान में जो घट रहा है, वह संभवत: ऐसा है जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी अथवा पूर्वानुमान नहीं लगाया था कि एक विजेता द्वारा आत्मदाह किए जाने की घटना इस क्षेत्र को राजनीतिक अस्त-व्यस्तता और अव्यवस्था की स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी।

अरब विद्रोह अब तक उन अपेक्षित सामाजिक-राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रहा है जिनके बारे में लोगों ने 2010 में इस विद्रोह के प्रारंभ होने के समय अनुमान लगाया था। इसके स्थान पर, इसने लाखों लोगों को मृत्यु, विस्थापन और उनकी गुमशुदगी ही प्रदान की है तथा ईरान और सउदी अरब के बीच क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने के अलावा क्षेत्र को पंथवाद, क्षेत्रीय, सैद्धांतिक और वर्ग संघर्ष के अभूतपूर्व स्तर तक ला खड़ा किया है। क्षेत्र में वर्तमान स्थिति तुर्की द्वारा रणनीतिक महत्वाकांक्षा के अभिनव प्रदर्शन, इजराइल के रणनीतिक और राजनीतिक सुदृढ़ीकरण, रूस द्वारा दर्शाई गई अकल्पनीय सैन्य भागीदारी और रणनीतिक दावे तथा क्षेत्र में अमेरिका और यूरोपीय सैन्य बलों की वापसी से अत्यंत पेचीदा बनी हुई है।

उपर्युक्त आंकड़ों के मद्देनजर, यह पत्र वर्तमान स्थिति के बारे में संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करता है और यह बताता है कि क्षेत्र के भविष्य में क्या लिखा है। यह पत्र पिछले छह वर्षों की प्रवृत्तियों को भी देखेगा और उस आधार का वर्णन करेगा जिस पर अरब के राजनीतिक और रणनीतिक भविष्य के बारे में अनेक संभावनाएं, यदि पूर्वानुमान नहीं, निहित होंगी, जिन पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा घटनाक्रमों का पूर्वानुमान लगाना आमतौर पर एक कठिन विज्ञान है तथा यह विशेषत: डब्ल्यूएएनए क्षेत्र जैसे जटिल अंचल में और भी कठिन बन जाता है। कोई भी यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है कि वर्तमान अव्यवस्था किस ओर ले जाएगी, अनिवार्यत: तब, जब स्थिति हर क्षण बदल रही है। वर्तमान विश्लेषण अब तक देखे गए पिछले छह वर्षों के यादृच्छिक संक्रमण पर आधारित है, इसमें कोई भी एक पूर्णत: विपरीत परिदृश्य की संभावना से इंकार नहीं कर सकता है जिसका वर्णन इस पत्र में किया गया है।

प्रस्तावना

वर्ष 2011 की वसंत ऋतु में अरब क्षेत्र में फैले विद्रोह की जड़ स्वतंत्र लोकतंत्र, रोजगार अवसरों के लिए लोगों की मागों और आकांक्षाओं तथा साथ ही उस गरिमा की आधारशिला पर निहित थी, जो दशकों से उनके लिए नदारद थी। ट्यूनीशिया में सिडी बॉजिड के छोटे शहर में विक्रेता द्वारा आत्मदाह कर लेने बाद लाखों लोगों द्वारा की गई पदयात्रा आधुनिक अरब विश्व के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी, जो क्षेत्र में लाखों लोगों द्वारा झेली जा रही दीर्घकालिक परेशानियों का ही प्रतीक थी। ट्यूनीशिया में भड़की इस चिंगारी ने मिश्र के श्री मुबारक को हिला दिया, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति को देश से भागने के लिए विवश कर दिया, यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह का प्रस्थान कराया और अंतत: लीबिया के कर्नल गद्दाफी को हटाए जाने और बाद में उनकी नृशंस हत्या का परिदृश्य दिखा।

लाखों लोगों की हत्याओं का परिणाम ऐसा था जिसकी कल्पना न तो विरोधकर्ताओं ने और न ही शासकों द्वारा कभी की गई थी। इस विद्रोह के प्रारंभिक दिनों में क्या हुआ, उस पर विश्वास करना संभव नहीं है क्योंकि राजनीतिक आयाम में, अरब विश्व ने अब तक केवल आजीवन राजतंत्र, आंशिक लोकतंत्र अनुदारवादी सैन्य तानाशाही की बिना विरोध स्वीकार्यता के सिवाए और कुछ नहीं देखा था, जो राजनीतिक व्यवहार का भाग बन गई थी।

परंतु सड़कों पर भयावह स्थिति अल्प समय तक ही कायम रही क्योंकि प्रथम बार निर्वाचित इस्लामी सरकार अधिक समय तक सत्ता में नहीं रही तथा केवल एक वर्ष के ही भीतर 2013 में, इसे एक ऐसे विद्रोह द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया जिसे कुछ विश्लेषक नागरिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। [2] ट्यूनीशिया में लोकतंत्र दृश्यमान है, परंतु एक अत्यंत नाजुक स्वरूप में जो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अल्पस्थायी देशों जैसे मिश्र ने इसके समकक्षियों की तुलना में मार्वात हतेम, मिश्र में 3 जुलाई के सैन्य विद्रोह पर वाद-विवाद : यह विद्रोह की परिभाषा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण विषय के बारे में है, सेंटर फॉर मेलेमोस्ट स्टडियर, 3 नवम्बर, 2013 http://static.sdu.dk/mediafiles/3/7/B/%7B37BCEEAA-C02D-4EA0-94DC-3C3F70F67C35%7DMH1113.pdf, (28 जनवरी, 2016 को एक्सेस किया गया)

अधिक सैद्धांतिक बलिदान दिए थे।[3] इस दौरान, सीरिया, लीबिया और यमन जैसे देशों ने कुल मिलाकर एक भिन्न मार्ग चुना जिसने वैकल्पिक लोकतांत्रिक आवाजों के उदय को ही दबा दिया था। इसके अलावा, वहां विद्यमान अव्यवस्थाओं ने भू-रणनीतिक उद्भव की प्रकृति पर अपने प्रभाव छोड़े और आज तक भी, इन देशों में विकास अरब क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।

इस विद्रोह के उपरांत अरब विश्व के रूपांतरण ने कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों का अनुभव किया है जिन्हें अहिंसक रूपांतरण के रूप में चिह्नित किया जा सकता है जैसे ट्यूनीशिया और मिश्र में हुआ था, इसमें संवैधानिक शासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की अधिक मात्रा थी जैसे मोरक्को और जार्डन में देखा गया था। स्थायी हिंसा थी जैसे सीरिया, यमन और लीबिया में उत्तरजीविता के लिए शासनों ने संघर्ष किया था, और विद्रोह को दबाने के लिए जीसीसी शासनों द्वारा उठाए गए कदम शामिल थें।परंतु बहुत जल्द, इन श्रेणियों के मध्य विभेद धुंधला पड़ गया तथा एक बेहतर भविष्य के लिए लोगों की आकांक्षाएं और आशाएं लगभग धूमिल हो गईं।

इस विद्रोह की पृष्ठभूमि में जिस बात ने क्षेत्रीय व्यवस्था को वस्तुत: परिवर्तित कर दिया था, वह सीरिया में हुआ विवाद था जहां विरोधों और अंसतोष ने बहुत जल्द पंथवादी गतिशीलता अर्जित कर ली थी तथा

वह दो पारंपरिक कड़े सैद्धांतिक, राजनीतिक और रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों सउदी अरब और ईरान के बीच क्षेत्र में प्रधानता अर्जित करने के युद्ध में परिवर्तित हो गई थी। सउदी अरब में शासन स्पष्टत: इराक में सद्दाम हुसैन के प्रस्थान तथा अफगानिस्तान में तालीबान को हटाए जाने के उपरांत उत्पन्न भौगोलिक गतिशीलता को बदलने के लिए जिसने सउदी अरब के स्थान पर क्षेत्र में ईरान को एक उच्च स्थिति प्रदान कर दी थी, किसी उपयुक्त अवसर का इंतजार कर रहा था। सीरिया ईरान का एक प्राचीन रणनीतिक भागीदार है तथा राष्ट्रपति असाद को हटाने में, सउदी अरब शासन एक रणनीतिक सहयोग की तलाश कर रहा था, अत:, सउदी अरब ने विद्रोही बलों को समस्त सहयोग प्रदान करना आरंभ कर दिया जिसमें वित्त-पोषण से लेकर असाद-विरोधी बलों को हथियार उपलब्ध कराना शामिल था। सउदी अरब कथित रूप से उन सैनिकों को वेतन उपलब्ध करा रहा था जिन्होंने असाद की सरकार की सेना से स्वयं को अलग कर लिया थाजैसे-जैसे सउदी अरब की इसमें भागीदारी बढ़ती गई, ईरान भी इसमें कूद पड़ा, जिसने दोनों ही मार्गों को और सीरियाई संकट की रूप-रेखा को धीरे-धीरे परिवर्तित कर दिया।

प्रधानता का यह युद्ध केवल ईरान और सउदी अरब के रूप में दो विरोधियों अथवा बाद में शामिल हुए तुर्की, कतर और यूएई के बीच ही सीमित नहीं रहा बल्कि यह रूस तक भी फैल गया जो दो से भी अधिक दशकों से क्षेत्र के रणनीतिक समीकरण से अलग रहा था। अमेरिका तो सदैव ही वहां मौजूद था तथा अमेरिका और रूस, दोनों ही ने स्वयं को सीरिया के रक्त-रंजित भू-भाग में रणनीतिक, राजनीतिक और राजनयिक विवादों में उलझा लिया था।

इसी प्रकार, लीबिया और यमन में हुआ रूपांतरण क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों और उनके आकाओं के लिए छद्म रूप से कार्य करने वालों की रणनीतिक अभिलाषाओं के लिए एक बंधक बन गया है क्योंकि दोनों ही राष्ट्रों ने स्वयं को जनजातीय, प्रादेशिक, नृजातीय और पंथवादी विवादों का क्षेत्र बना लिया है जिससे राजनीतिक एकता और स्थिरता की संभावनाएं आहत हुई हैं।

अरब विद्रोह से उत्पन्न होने वाली लोकतांत्रिक आकांक्षाएं रणनीतिक पुनर्विन्यास और उद्भव के लिए प्रादेशिक युद्ध में परिवर्तित हो गई हैं जिसमें क्षेत्र का लगभग प्रत्येक राष्ट्र या तो स्वयं शामिल हो गया है अथवा अनिच्छा के बावजूद उसमें घसीट लिया गया है। अरब विद्रोह के प्रभाव ने राष्ट्रीय प्रणाली को भी प्रभावित किया है तथा आज यह न केवल क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है बल्कि इसने क्षेत्र को पुन: वैश्विक राजनीतिक के चंगुल में भी ला दिया है, जिससे शीत-युद्ध के युग का स्मरण हो उठता है। भिन्न-भिन्न देश भिन्न-भिन्न हितों के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसने क्षेत्र को एक दोरोहे पर लाकर खड़ा कर दिया है तथा इसे न केवल पड़ोसियों बल्कि दूर-दराज के देशों से चुनौतयों के भिन्न पिटारे का सामना करने के लिए विवश कर दिया है। अरब विश्व में शाश्वत रूपांतरण आर्थिक, सामाजिक और भू-रणनीतिक विवक्षाएं लेकर आया है। इसका परिणाम अनेक वैकल्पिक व्याख्याएं उपलब्ध करा सकता है जो किसी देश के लिए मूल्यवान हो सकती है, परंतु अनेक देशों के लिए हानिकारक हो सकती हैं।

निरंतर उथल-पुथल के छह वर्ष और इसके भू-रणनीतिक परिणाम

क्षेत्र ने पिछले छह वर्षों में व्यापक भू-राजनीतिक रूपांतरण देखा है। अरब विश्व लोकतंत्र की महान आशा से विखंडन, असुरक्षा और भंगुरता की स्थिति की ओर रूपांतरित हुआ है। पिछले छह वर्षों के घटनाक्रम ने राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है। उभरती हुई राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के भीतर अनेक परिवर्तन आए है, जो संपूर्ण क्षेत्र की भू-राजनीतिक को प्रभावित कर रहे हैं, जोकि वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राज्यों के मध्य सुरक्षा चिंताओं और तनाव में वृद्धि हुई है तथा इसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष

तनाव उत्पन्न हुआ है जिसने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा को चुनौती दी है। क्षेत्र एक नई सुरक्षा व्यवस्था के अभ्युदय का साक्षी भी रहा है जहां शक्ति और प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है तथा उन्हें राज्य और गैर-राज्यकर्ताओं के मध्य वितरित किया गया है।

घटनाक्रम

यहां इन देशों में पिछले छह वर्ष के दौरान घटित हुए घटनाक्रमों का संक्षिप्त और वर्षवार ब्योरा देना समीचीन प्रतीत होता है, जिन्होंने न केवल संबंधित राष्ट्रों की घरेलू राजनीतिक प्रगति को प्रभावित किया बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति के उभरते हुए राजनीतिक और रणनीतिक परिदृश्य पर भी गहरा प्रभाव डाला।

वर्ष	प्रमुख घटनाएं
मिश्र	
2011	समूचे राष्ट्र में शासन-विरोधी प्रदर्शन, राष्ट्रपति मुबारक ने पद छोड़ा, एससीएएफ ने परिवर्ती शासन संभाला, संविधान के प्रकृति पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह संचालित किया गया, अल-गंजौ के अधीन नेशनल यूनिटी सरकार गठित हुई।
2012	एफजेपी और अल-नोर का इस्लामी गठबंधन संसदीय चुनावों में विजेता बना ; संवैधानिक न्यायालय ने संसद का विघटन किया; श्री मोर्सी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए इस्लामी नेतृत्व वाली संवैधानिक समिति ने मसौदा संविधान का अनुमोदन किया।
2013	राष्ट्रपति मोर्सी ने डिक्री पारित की तथा स्वयं को न्यायिक समीक्षा से मुक्त किया ; व्यापक विरोध और सेना के हस्तक्षेप के बाद राष्ट्रपति मोर्सी को सत्ता से हटाया गया; श्री एडले मंसूर अंतरिम राष्ट्रपति बने तथा भावी मार्ग की घोषणा की गई; संविधान को शून्य घोषित किया गया; मोर्सी-प्रिय प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए; एमबीएच को आतंकी संगठन घोषित किया गया।
2014	एक राष्ट्र-व्याापी जनमत-संग्रह में नए संविधान को अनुमोदित किया गया़जनरल एल-सिसी राष्ट्रपति बने; 500 से अधिक एमबीएच सदस्यों को मृत्यु की सजा सुनाई गई तथा एक अन्य न्यायालय ने 600 से अधिक एचबीएच काडरों को हिंसा के लिए मृत्युदंड दिया।
2015	अनेक कानून पारित किए गए जिनमें लोगों की राजनीतिक गतिविधियों के विरुद्ध सतर्कता वृद्धि की गई; मोर्सी को उनके अन्य सैकड़ों समर्थकों के साथ हिंसा भड़काने के लिए मृत्युदंड सुनाया गया; एक नई राष्ट्रीय संसद निर्वाचित हुई; महा अधिवक्ता की हत्या कर दी गई और देश में हिंसा की नई लहर फैल गई ; रूसी विमान को सिनई में गिराया गया तथा आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली।
2016	मिश्र ने दो रणनीतिक लाल सागर द्वीपों को सउदी अरब को सौंपने की घोषणा की, जिससे आक्रोश और असंतोष फैल गया; मिश्र के एक अपील न्यायालय ने मोर्सी के मृत्युदंड को रद्द कर दिया।
लीबिया	

2011	लीबिया के अनेक शहरों में कदाफी-विरोधी प्रदर्शनों में अनेक लोग मारे गए ; ईयू ने हथियार प्रतिबंध घोषित किया तथा 'कोई उड़ान नहीं क्षेत्र' अधिरोपित किया गया; यूएनएससी ने 'संरक्षण उत्तरदायित्व' संकल्प पारित किया; नाटो के अभियान ओडेसी डॉन ने हवाई हमले प्रारंभ किए; कदाफी इस अभियान में मारे गए; नेशनल ट्राजींशन काउंसिल को लीबिया की राष्ट्रीय सरकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
2012	आतंरिक-आदिवासी और क्षेत्रीय संघर्षों में वृद्धि हुई; बेंघाजी के लिए स्वायत्तता हेतु अभियान प्रारंभ हुआ तथा पूर्व और पश्चिम के बीच भौगोलिक पृथक्कीकरण के बारे में कोई नया युद्ध नहीं हुआ; लीबिया में अमेरिकी राजदूत को मार डाला गया; नई नेशनल एसेम्बली (जीएनसी) निर्वाचित हुई तथा टीएनसी को विघटित किया गया।
2013	प्रधानमंत्री अली जेदान का त्रिपोली में एक होटल से उनकी विफलता के कारण हथियारबंद सैनिकों द्वारा अपहरण कर लिया गया और बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया।
2014	अत्यंत कम प्रतिभागिता के साथ संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए ; हफ्तार का उदय राजनीतिक प्रक्रिया के लिए एक प्रमुख चुनौती बना ; उन्होंने लीबियाई राष्ट्रीय संसद (जीएनसी) के एकपक्षीय विघटन की घोषणा की और राष्ट्रपति की समिति गठित की ; हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए चुनाव आयोजित किए गए ; हफ्तार ने इस्लामियों और उनके संगठन 'लीबिया डॉन' को पराजित करने केलिए आप्रेशन डिग्निटी प्रारंभ किया; राजधानी त्रिपोली डॉन के कब्जे में आ गई जिसने पहले जीएनसी को एकमात्र वैध निकाय घोषित किया था; एचओआर बलों ने अपनी राजधानी तबरक स्थानांतरित कर दी।
2015	ताबरक सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली जबकि उमर अल-हसी, पूर्व जीएनसी सदस्य ने त्रिपोली में नेशनल सैल्वेशन सरकार का गठन किया; अनेक तेल क्षेत्रों पर आईएसआईएस का कब्जा हो गया तथा आईएसआईएस के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में सिर्टे की भांति शहर का अभ्युदय हो गया; इक्कीस इजप्टियन कॉप्टिक्स लीबिया में मारे गए तथा मिश्र ने डिर्ने शहर पर हवाई हमले आरंभ किए अमेरिका ने आईएसआईएस-विरोधी हवाई हमले किए; मोरक्को में नया राजनीतिक करार हस्ताक्षरित किया गया जिसे लीबियाई राजनीतिक करार कहा जाता है
2016	अमेरिका द्वारा समर्थित गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकार्ड की घोषणा की गई तथा फयेज-एल-सर्र को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। एचओआर त्रिपोली पहुंचा परंतु सैल्वेनियन सरकार ने सराज सरकार को मान्यता देने से इंकार कर दिया।
सीरिया	
2011	समूचे राष्ट्र में छिड़े व्यापक विरोधों के उपरांत राष्ट्रपति मसाद ने सरकार को बर्खास्त कर दि तथा 48 वर्ष पुराने आपातकालीन कानून की समाप्ति हुई; सीरिया को अरब लीग से निलंबत किया गया तथा अमेरिका और ईयू ने प्रतिबंधों को कड़ा किया; फ्री सीरियन आर्मी और सीरियन नेशनल काउंसिल प्रमुख विरोधी बल बने।
2012	यूएनएससी ने पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत कोफी अन्नान द्वारा तैयार गैर-बाध्यकारी शांति योज का अनुसमर्थन किया; तुर्की के विमान को सीरियाई वायुसेना द्वारा मार गिराया गया; लगभग तीन सौ नागरिक रसायन हमले में मारे गए ; कतर में नेशनल कोलीशन फॉर सीरियन रेवोलुशनरीज़ का गठन किया गया; अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और जीसीसी ने इसे सीरियाई

	लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। कोफी अन्नान को सीरिया में यूएन-अरब लीग का राजदूत नियुक्त किया गया तथा बाद में उनके स्थान पर लखदार ब्राहिमी को भेजा गया जिनका शांत का प्रस्ताव विफल हो गया था; जिनेवा सीरिया में युद्ध समाप्त करा पाने में असफल रहा।
2015	अमेरिका और यूके ने विद्रोह बलों को घातक हथियारों की आपूर्ति निलंबित; इस्लामी बलों ने पश्चिम-समर्थित फ्री सीरिया आर्मी द्वारा कब्जाए गए क्षेत्र को अपने हाथों में लिया।
2017	सीरिया के रासायनिक हथियारों को सीरियाई रासायनिक हथियार उन्मूलन फ्रेमवर्क के अंतर्गत नष्ट कर दिया गया; अमेरिका द्वारा समर्थित जिनेवा-III विफल रही; आईएसआईएस ने एलेपो से लेकर दियाला शहर तक के भू-भाग में खिलाफत की घोषणा की; अमेरिका ने पांच राष्ट्रों के साथ आईएसआईएस के विरुद्ध आक्रमण प्रारंभ किया।
2015	रूस ने आईएसआईएस के विरुद्ध प्रथम हवाई हमला प्रारंभ किया; वियना शांति वार्ता विफल हुई।
2016	अमेरिका की मध्यस्थता में जिनेवा में आयोजित शांति वार्ता (जिनेवा III) विफल रही; सीरियाई सरकार ने पल्मायरा शहर वापस लिया तथा एलेपो शहर पर पुन: कब्जा किया; सीरिया पर चर्चा करने के लिए ईरान, रूस, तुर्की की मास्को में बैठक हुई।
	यमन
2011	राष्ट्रपति सालेह के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे; जीसीसी राष्ट्रों ने राष्ट्रपति सालेह को अपदस्थ करने की मध्यस्थता की परंतु हिंसा जारी रही; तीन माह के लिए राष्ट्रीय एकता सरकार का गठन किया गया तथा उपराष्ट्रपति मंसूर हादी दो वर्ष के लिए अंतरिम राष्ट्रपति बने।
2012	सप्लेह का स्थान लेने के लिए मंसूर हादी 99 प्रतिशत से अधिक मतों के साथ राष्ट्रपति निर्वाचित हुए; दक्षिणी यमन की स्वायत्तता के लिए एक नए आंदोलन का आरंभ हुआ।
2013	यूएन समर्थित जीसीसी ने नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 500 राजनीतिक हस्तियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रीय वार्ता आयोजित की।
2014	विद्रोही हैतियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया तथा प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया, परंतु उसे संसद द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।
2015	राजधानी पर तथा उनके घर पर हैतियों द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण यमन राष्ट्रपति हादी ने इस्तीफा दिया ; राष्ट्रपति हादी दक्षिण शहर एडेन भाग गए ; बाद में उन्होंने एक निर्वासित राष्ट्रपति के रूप में रहने के लिए सउदी अरब की शरण ली; हौतियों ने संसद को भंग कर दिया तथा राष्ट्र को चलाने के लिए पांच सदस्यीय राष्ट्रपति परिषद का गठन किया; यमन के हौथियों के विरुद्ध सउदी अरब और उसके गठबंधन देशों द्वारा 'स्टार्म ऑफ रीसॉल्व' अभियान आरंभ किया।
2016	अमेरिका द्वारा प्रायोजित कुवैत वार्ताएं विफल रहीं।

प्रादेशिक व्यवस्था में दृश्यमान परिवर्तनों में अनेक प्रवृत्तियां शामिल हैं तथा उनमें से सर्वाधिक प्रमुख प्रवृत्ति दीर्घकालिक तानाशाहों के विरुद्ध आंतरिक असंतोष, गहराता पंथवादी कलह और क्षेत्रीय राजनीति की बदती सैद्धांतिक प्रकृति, सीरिया, इराक और यमन के संकट में ईरान और सउदी अरब के बीच प्रतिद्वद्विता के अलावा तुर्की और इजराइल जैसी क्षेत्रीय शक्तियों की बढ़ती भूमिका तथा सबसे महत्वपूर्ण, कतर और यूएई जैसे राष्ट्रों की क्रमिक सुदृढ़ता थी[6]।

इस दौरान इस परिवर्तित होते राजनीतिक परिदृय में, हम पुरानी राजनीतिक हैसियत हासिल करने के लिए मिश्र की नई इच्छा को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मिश्र अपनी खोई हुई राजनीतिक और रणनीतिक स्थिति को पुन: प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है जो कि उल्लेखनीय रूप से पिछले दो दशकों में कम हुई थी। विद्रोह तथा उसके परिणाम, जिसके फलस्वरूप सेना के लिए एक नई विस्तारित भूमिका की आवश्यकता हो गई थी, ने इसकी इच्छा को बलवती कर दिया था तथा प्राचीन रणनीतिक पकड़ को पुन बहाल करने के लिए नई उम्मीद को हवा दे दी थी। यह भी सच बन गया था कि क्षेत्र में शांति तब तक भ्रम थी, जब तक सीरियाई संकट का समाधान न हो जाए तथा संकट का समाधान भी एक जटिल कवायद बन गया था क्योंकि उसमें अनेक हितधारक तथा उसके लाभप्रद परस्पर जुड़े संबंध भी शामिल हो गए थे।

तुर्की और इजराइल भी क्षेत्रीय रूपांतरण में उल्लेखनीय और निर्णायक भागीदारों के रूप में उभरे थे जिसकी क्षेत्र की भू-रणनीतिक स्थिति पर गहन प्रभाव पड़ने की संभावना थी। इस उथल-पुथल के तत्काल बाद, तुर्की ने अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने में कोई समय नष्ट नहीं किया तथा अपने पड़ोसियों के साथ 'शून्य समस्या' की अपनी अति-प्रशंसनीय नीति की कीमत पर रणनीतिक रूप से कार्यवाही करनी प्रारंभ कर दी। यह न केवल राष्ट्रपति असाद को परास्त करने की मांग करने वाला पहला राष्ट्र था, बल्कि यह देश में विद्रोही शक्तियों के संगठन की मेजबानी करने वाला पहला राष्ट्र था। तुर्की सीरिया के नए उभरते परिदृश्य में एमबीएच को समायोजित करने का अवसर तलाश रहा था, परंतु असाद ने एमबीएच के साथ शक्तियों का बंटावारा करने की तुर्की की मांग से इंकार कर दिया[7]। तुर्की सीरिया के संबंध में अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा था।

इसी प्रकार, इजराइल इस अस्त-व्यस्तता का प्रमुख लाभार्थी प्रतीत होता है तथा इस अनिश्चित स्थिति द्वारा इसे रणनीतिक लाभ हासिल होने की संभावना है। दमस्कस के बाहरी इलाके पर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र पर फरवरी, 2013 में इजराइल का हवाई हमला[8] राष्ट्रपति असाद की सरकार को कमजोर करने के प्रयास की अभिव्यक्ति थी। मोर्स के शासन की समाप्ति इजराइल के लिए राहत का एक अन्य स्रोत थी क्योंकि इस्लाम के अधिक समय तक सत्ता में रहने से उस विद्यमान शांति संरचना के प्रभावित होने का खतरा था, जो उस समय इजराइल के लिए लाभप्रद थी। इसके अलावा, क्षेत्र में होने वाला कोई विवाद और बढ़ता आतंकवाद इसके सुरक्षा उपायों में वृद्धि करने वाला ही होता जो सदैव ही इजराइल के लिए शक्ति का स्रोत रहा है तथा जिसने इसकी सुरक्षा संरचना और हथियारवादी को औचित्यपूर्ण ठहराया है।

अब तक सीरिया में गृह युद्ध ने 400,000 लोगों की जानें ली हैं [9] तथा स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, आधी जनसंख्या को मानवीय सहायता की आवश्यकता है।[10] सीरिया एक आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त राज्य से एक पूर्णत: युद्धग्रसित अर्थव्यवसथा की ओर

उभरा है, जिसने अस्त-व्यस्त परिवेश का सृजन किया है तथा आर्थिक अवसंरचना पूरी तरह से नष्ट हो गई है। यदि देश पांच प्रतिशत की सामान्य दर पर विकास करता है, तो युद्ध से पूर्व के जीडीपी स्तर को हासिल करने में 37 वर्ष लगेंगे।[11]

क्षेत्र में वर्तमान स्थिति को समझने का श्रेष्ठ ढांचा 'शीत युद्ध' का ढांचा है जहां दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी- ईरान और सउदी अरब प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए संबंधित शासकों को उकसा रहे हैं तथा राज्य-विरोधी तत्वों को भड़का रहे हैं। दोनों देशों के बीच भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने समूचे क्षेत्र में शक्ति के संघर्ष को प्रारंभ कर दिया है तथा क्षेत्र को भू-राजनीतिक खेल में बदलकर रख दिया है।[12] क्षेत्र का भू-रणनीतिक मानचित्र निर्धारित किया जा रहा है तथा प्रत्यक्षत: स्थानों को पंथवाद के रूप में दर्शाया जा रहा है, जबकि वास्तविक सत्यता अन्य कारकों द्वारा भी प्रदर्शित होती है। यदि हम इन दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता को केवल पंथवादी आयाम से अथवा शिया-सुन्नी विविधता से देखेंगे, तो यह एक पक्षपातपूर्ण और अपर्याप्त दृष्टिकोण होगा। क्षेत्र की पंथवादी जनसांख्यिकी प्रकृति और स्वाभाविक प्रकृति पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों ने, नि:संदेह ही, वर्तमान संकट में एक आनुपातिक भूमिका का निर्वहन किया है, परंतु केवल पंथवाद पर ही ध्यान-केन्द्रित किया जाना मामले के तथ्यों को विकृत कर देगा। यह स्थिति तब और प्रासंगिक बन जाती है, जब हम खुर्दों को एक महत्वपूर्ण कर्ता के रूप में देखते हैं और सुन्नी पंथवादी नस्ल के स्थान पर उनकी नृजातीय राष्ट्रवादी पहचान पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हैं।

यही बात मुस्लिम ब्रदरहुड (एमबीएच) के लिए भी सत्य है जो एक सुन्नी इस्लाम संगठन है, जो सउदी अरब के लिए चिंता और आकांक्षा का निरंतर स्रोत बना हुआ है, जो एक प्रमुख सुन्नी क्षेत्र है, जिसने 2013 में मिश्र में उन्हें सत्ता से हटाने में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाई थी। ईरान इराक में कुछ खुर्दिश समूहों के साथ बेहतर संबंध रखता है तथा सुन्नी-बहुल हमास में इसका समर्थन जग-जाहिर है। सउदी अरब ने इराक में आयाद अलावी की पार्टी को भी पूर्ण समर्थन प्रदान किया था, जो स्वयं जन्म से एक शिया है, परंतु वह इराक में 2005 और 2010 के चुनावों में सेकुलर फ्रंट का नेता था।[13] सीरिया का बाथवादी धर्म-निरपेक्ष शासन इस्लामी ईरान को पसंद नहीं करता था, परंतु इराक और इजराइल के रूप में साझे शत्रुओं ने उनके बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित कर दिए। सीरिया में एलवाइट समृद्ध-वर्ग का शासन अनेक शियाओं के लिए अपधर्मी पंथ है।

क्षेत्र में विवाद का मौजूदा आयाम द्विआधारी ईरान-सउदी रणनीतिक दृष्टिकोण द्वारा उत्प्रेरित है। जबकि ईरान खाड़ी में एक केन्द्रीयकृत सुरक्षा दृष्टिकोण हासिल करना चाहता है, वहीं इसके विपरीत, सउदी अरब क्षेत्र में अपना शासन हासिल करने के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी गठबंधन देशों जैसे यूके से बाह्य सहायता हासिल करने को तरजीह देता है। सीरिया में गृह युद्ध ने समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को उसमें घसीट लिया है तथा घरेलू विवाद, पराराष्ट्रीय संबंधों और प्रादेशिक आकांक्षाओं के बीच गहन संबंध को प्रदर्शित किया है।[14]

सीरिया में जो कुछ घट रहा है, वह यह है कि स्थानीय कर्ता ऐसी शक्तियों की ओर देख रहे हैं जो कतिपय परिमाण में परस्पर सैद्धांतिक, पंथवादी, समान और राजनीतिक संबंध साझे करते हों और जो इसके बदले में उन्हें स्थानीय कर्ताओं के साथ उनके संबंधों को सुदृढ़ बनाने में सहायता प्रदान करते हों। ईरान और सउदी अरब, दोनों ही अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में इन सैद्धांतिक और पंथवादी कारकों का प्रयोग कर रहे हैं। सीरिया के माध्यम से लेबनान से इराक तक विद्यमान राज्यों की कमजोरी और

राज्यों की विफलता का सिलसिला, नए अरब विश्व के शीतयुद्ध में पंथवाद की विशेषता का वर्णन करता है, जिसकी वंशावली इराक की सद्दाम-उपरांत राजनीति में स्थित है। सीरिया तथा क्षेत्र में रणनीतिक समीकरण को जिस बात ने और खराब किया है तथा उसे विकृत बनाया है, वह रूस की प्रतिभागिता है। रूस ने न केवल असाद के शासन के आसन्न पतन का बचाव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बल्कि उसने क्षेत्र के राजनीतिक और रणनीतिक मार्ग में परिवर्तन करने के लिए ईरान के साथ एक नया गठबंधन भी स्थापित किया था। रूस की इसी पहुंच ने तुर्की तथा अन्य जीसीसी राष्ट्रों की भूमिका को सीमित किया, जो राष्ट्रपति असाद को हटाते हुए क्षेत्र में रणनीतिक यथास्थिति में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे।

इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इराक और अफगानिस्तान से क्रमश: सद्दाम हुसैन और तालीबान शासन को हटाया जाना सीरिया में तथा समग्र रूप से क्षेत्र में ईरान और सउदी अरब के बीच वर्तमान प्रतिद्वंद्विता का वर्णन करता है। अमेरिका पर हुए 9/11 हमलों के उपरांत ईरान के पड़ोस से दो सुन्नी शासनों, इराक और अफगानिस्तान को हटा दिया गया। सद्दाम को हटाए जाने से पूर्वी अरब विश्व (इराक) में इरानियों के प्रभाव में वृद्धि हुई तथा सीरियाई संकट सउदी अरब के लिए असाद को हटाते हुए इस प्रभाव को संतुलित करने का अवसर लेकर आया, यदि वे क्षेत्र में ईरान के प्रभाव को पूरी तरह वापस नहीं कर पा रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2011 तक सउदी अरब अपने पड़ोस में समस्त अस्थिर शक्तियों द्वारा घिरा हुआ था : पूर्व में बहरीन, पश्चिम में सीरिया, दक्षिण में यमन तथा उत्तर में निरंतर अस्थिरता वाला इराक।

इसके अलावा, सउदी अरब ने मिश्र में अपना एक घनिष्ठ साथी पहले ही खो दिया था जब अरब विद्रोह के मध्य लोगों के बढ़ते हुए दबाव के कारण मुबारक ने सत्ता छोड़ दी थी। सउदी अरब हेजबुल्ला को भी वश में रखने में असफल रहा जो लेबनान में ईरानियों का आश्रित था तथा इराक के रणनीतिक भू-भाग पर पहले से ही ईरान द्वारा कब्जा जमाया हुआ था। यहां तक कि बढ़ते हुए ईरानी प्रभाव का विरोध करने के उद्देश्य से 2006-2007 में इराक में आईएसआईएस के बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका द्वारा सृजित अल-सहवा संगठन भी सउदी अरब के लिए कोई अपेक्षित रणनीतिक लाभ दे पाने में समर्थ नहीं रहा था। मिश्र और ट्यूनीशिया के इस्लामियों की विजय भी सउदी अरब के लिए एक अन्य झटका लाई थी क्योंकि इस्लाम और लोकतंत्र के संयोजन ने न केवल सउदी अरब के दशक पुराने राजतंत्र के लिए भय और चिंताएं उत्पन्न की थीं बल्कि इसने इरानी सैद्धांतिक आडम्बर को तथा क्षेत्र में इस्लाम के प्रभाव को भी सुदृढ़ बनाया था, जिसके पास क्षेत्र में सउदी अरब की स्थिति को प्रभावित करने की संभावना मौजूद थी। सउदी अरब की मुख्य चिंता यह थी कि अब तक ईरान उनसे बेहतर दिखा है, तथा उसने पूर्व में अनेक प्रतिबंधों को झेलते हुए अपने रणनीतिक-राजनीतिक वर्ग का पूर्ण उपयोग किया है।

इस पृष्ठभूमि में, सउदी प्रशासन पूर्णत: सीरियाई विद्रोही बलों की ओर था। सउदी अरब ने तत्काल ही विद्रोही सेनाओं को अपना लिया था तथा पैसे और हथियारों से फ्री सीरियन आर्मी की सहायता की, तथा अन्य प्रतिरोधी संगठन खाड़ी के समृद्ध राष्ट्रों जैसे कतर और यूएई द्वारा तैयार किए जा रहे थे। तुर्की और कतर ने इस्लामी बलों जैसे सीरियाई एमबीएच को समर्थन देने का निर्णय लिया जो सउदी अरब समर्थित सलाफिस्टों के समीप नहीं था। सउदी अरब और तुर्की की श्री असाद और ईरान के विरुद्ध शक्तिशाली मोर्चा स्थापित करने की सुस्पष्ट असमर्थता का श्रेय क्षेत्र में उभरती राजनीतिक और रणनीतिक स्थिति के संबंध में स्वयं सुन्नी विश्व[15] के मध्य एकमत के अभाव तथा गहन विभेदों का दिया जा सकता है। कतर द्वारा एमबीएच को दी जाने वाली सहायता में निरंतर वृद्धि से जीसीसी के मध्य मतभेद गहरे हो गए जिसके परिणामस्वरूप मार्च, 2014 में सउदी अरब, यूएई और कुवैत द्वारा कतर से अपने राजदूतों को वापस बुलाने के लिए एक समन्वित आह्वान किया

गया।[16] एक संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी के अनुसार जिसे पॉल डानाहेर द्वारा उद्धृत किया गया है, "यहां तक कि छद्म युद्ध भी वहां समन्वित नहीं था। तुर्की अपने स्वयं के अनुयायियों को समर्थन दे रहे थे, कतर अपने और सउदी भी अपने ही लोगों का समर्थन दे रहा था तथा आगे चलकर यह अत्यंत घातक सिद्ध होने वाला[17] था।

परंतु सउदी अरब बहरीन में ऐसे ही विद्रोह को सहने के लिए तैयार नहीं था तथा विरोध की प्रांरभिक अवस्था पर ही, उसने विद्रोहियों को कुचलने के लिए जीसीसी सेनाएं भेज दी तथा लीबिया में नाटो के हस्तक्षेप को समर्थन दिया। यमन में सउदी अरब ने शक्ति के सुचारू अंतरण के समर्थन के लिए त्वरित कदम उठाए, परंतु जल्द ही वह लड़खड़ा गया तथा ईरान के बढ़ते हुए रणनीतिक प्रभाव से बाहर नहीं रह पाया।

यह केवल सउदी-ईरान प्रतिद्विद्वता ही नहीं है जो पिछले छह वर्षों से इस रूपांतरण की विशेषता रही है। इसमें एक अन्य प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति तुर्की है, जिसकी अभी हाल तक, पश्चिमी देशों द्वारा लोकतांत्रिक दृश्टि से सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से उन्नत देश के रूप में सराहना की जा रही थी। अरब विद्रोह से एक दशक पूर्व तुर्की ने स्वयं को क्षेत्र में एक उल्लेखनीय और विशाल शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था जिसमें इसका 'पड़ोस के साथ शून्य-समस्या' का प्रसिद्ध सूत्र भी शामिल था। यह फिलीस्तीन-इजराइल संकट, इजराइल-सीरिया विवाद तथा ईरान के परमाणु मुद्दे पर मध्यस्थ भी रहा था। तुर्की की रणनीतिक अभिलाषा राष्ट्रपति सद्दाम के प्रस्थान के उपरांत सुस्पष्ट थी जब उसने क्षेत्र में बढ़ते ईरानी प्रभाव को रोकने के लिए प्रयास किए थे। रूपांतरण के दौरान, एक हित के क्षेत्र के रूप में क्षेत्र के साथ किए गए तुर्की के व्यवहार ने इसे प्रभाव-क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया।[18] तत्कालीन प्रधानमंत्री एर्डोगन क्रांति के उपरांत मिश्र, ट्यूनीशिया और लीबिया का दौरा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा उन्होंने ट्यूनीशिया और मिश्र में इस्लामी लहर के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी। परंतु बहुत जल्द अनेक लोगों द्वारा तैयार किया गया तुर्की मॉडल मृगतृष्णा साबित हुआ। यह मृगतृष्णा इसलिपए बना कि अधिकांश देशों में विद्रोह छिड़ गए थे, और वे जल्द ही तानाशाही के तहत आ गए तथा वहां हिंसा और विवाद व्याप्त हो गया। इसके अलावा, तुर्की भी अपने पूर्व के रोमानीवाद को अपना पाने में विफल रहा तथा उसने कट्टर इस्लामी स्वर और आशय से परिपूर्ण अपनी रणनीतिक आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने में समय नष्ट नहीं किया जिसके अनेक देश उससे रुष्ट हुए जैसे सउदी अरब, ईरान और मिश्र।

तुर्की की विदेश नीति 'शून्यन समस्या' का प्रमुख लक्ष्य जल्द ही अदृश्य हो गया तथा सीरिया के मामले को छोड़कर इसे कहीं भी अधिक घोषित नहीं किया गया। तुर्की सीरिया में राष्ट्रपति असाद के त्यागपत्र की मांग करने वाला क्षेत्र का प्रथम राष्ट्र था। इसने सितम्बर, 2011 में सीरिया के साथ अपने संबंधों की समाप्ति की घोषणा की तथा यह सीरिया में असाद-विरोधी उग्र बलों को भेजने का मुख्य द्वार बना गया, तथा सीरिया-तुर्की सीमा को 'जिहाद राजमार्ग' के रूप में जाना जाने लगा। [19] तुर्की ने असाद विरोध इस्लामी सेनाओं (सीरियाई एमबीएच) के साथ प्रगाढ संबंध विकसित किए जबकि कतर, सउदी अरब और यूएई ने मिश्र विद्रोही धड़ों को समर्थन दिया। तुर्की ने केवल सीरिया के गृह-युद्ध में भागीदार बना, बल्कि वह राज्य विरोधी तत्वों सहित विभिन्न बाह्य शक्तियों के परस्पर मामलों में भी शामिल था। तुर्की सुन्नी धड़ों के बीच अनेक मतभेद होने के बावजूद उनके प्रादेशिक धड़े के साथ जुड़ा रहा। इसने जुलाई, 2013 में मिश्र में एमबीएच-प्रेरित सरकार के हटाए जाने के उपरांत क्षेत्र में अपना इस्लामी प्रभाव भी खो दिया था तथा सउदी अरब भी सीरिया में इस्लामी संगठनों को तुर्की द्वारा दिए जा रहे सहयोग से खिन्न था।

तुर्की मिश्र में सेना के विद्रोह का सर्वाधिक कट्टर आलोचक था तथा इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री एर्डोगन ने कहा था कि जो विद्रोह नहीं कहते हैं, वे विद्रोह के समर्थक हैं।[20] विद्रोह की आलोचना करने तथा इस्लाम का पक्ष लेने के कारण सेना का शासन उसका विरोधी हो गया, अत: क्षेत्र में एक अन्य सुन्नी धड़े के साथ उसके संबंध कटु हो गए। वर्तमान में, सीरिया और मिश्र में तुर्की का कोई राजदूत नहीं है तथा, हाल में, इसने इजराइल में एक राजदूत नियुक्त किया है। यूनान, इजराइल, साइप्रस और मिश्र के बीच नए उभरते हुए गठबंधन को तुर्की द्वारा भूमध्यसागर में उसके आर्थिक हितों को न्यून बनाने के रूप में देखा गया है। ईरान के साथ उसके संबंध उसकी ईरान नीति के कारण स्थिर नहीं है, तथा यही बात खुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट(केआरजी) के मामले में भी सत्य है।

जिहादियों के प्रति तुर्की की नीति ने भी इसे क्षेत्रीय और वैश्विक दृष्टि से पृथक किया है तथा रूस के लड़ाकू विमान को गिराने से यह लगभग युद्ध के मुहाने तक पहुंच गया था। खुर्दिश मामले में इसकी व्यापक सहभागिता के कारण नया जीवन प्राप्त किया, जिसने खुर्दिश बलों को अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस अस्थिर क्षेत्र का दोहन करने का अवसर प्रदान किया है। खुर्दिश सेनाओं तथा अमेरिका द्वारा नेतृत्व किए गए गठबंधन का आईएसआईएस के विरुद्ध छेड़ा गया समन्वित संघर्ष जिसका उद्देश्य उसके नियंत्रण से निकालकर कुबानी को सीरिया में वापस लाना है, तथा तुर्की की उभयमुखी भूमिका ने तुर्की के खुर्दों और सरकार के बीच वैमनस्य को भड़का दिया है, तथा बाद में, इसके फलस्वरूप अमेरिका और तुर्की के बीच पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हुए।

इजराइल और मिश्र जैसे कुछ अन्य राष्ट्र भी हैं, जिन्होंने क्षेत्र में संक्रमण को न केवल प्रभावित किया है, बल्कि वे उभरती हुई क्षेत्रीय व्यवस्था में अपनी स्थिति को पुन: सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त कार्य कर रहे हैं। मिश्र सदैव ही अपनी जनसांख्यिकी, अपनी भू-रणनीतिक अवस्थिति तथा स्वेज नहर पर अपने नियंत्रण के कारण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, जो तेल और गैस की आपूर्ति के लिए प्रशा की खाड़ी और यूरोप के बीच संपर्क बिंदु रही है।

पिछले छह वर्षों में, देश ने अपने भू-रणनीतिक क्षेत्र में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। मुबारक के जाने के तत्काल उपरांत तथा इस्लाम के सत्ता पर काबिज होने पर, क्षेत्र में इसके सबसे सुदृढ़ रणनीतिक मित्र-राष्ट्र इजराइल के साथ संबंध अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके हैं। मिश्र ने ईरान में एक नया साथी ढूंढ लिया है जो देश की विदेश नीति की पुस्तकों में एक लंबे समय से गायब देश था। मुबारक के प्रस्थान के मात्र दस दिन के भीतर, दो ईरानी पोतों को 1979 के बाद पहली बार स्वेज नहर के माध्यम से भू-मध्यसागर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। मिश्र के विदेश मंत्री नबील अल अरबी ने वाशिंगटन पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार(मार्च-जून, 2011) में कहा कि ईरान के साथ मित्रता उनकी नीति का भाग है तथा यह दावा किया कि ईरान शत्रु देश नहीं है। मिश्र भी फिलीस्तीन के लिए अपनी नीति को पुन: परिभाषित कर रहा है। श्री नबील अल-अरबी ने मार्च, 2011 में एक हमास शिष्टमंडल का स्वागत किया, तथा न केवल रफाह के साथ अपनी सीमा को खोला बल्कि इसे बंद किए जाने को एक अनुचित बात बताया।[21]

परंतु ये सभी पहलें एक वर्ष के भीतर ही वापस हो गई जब इस्लामी सरकार हटा दी गईं, और एक बार फिर इजराइल और अमेरिका के बीच संबंध विद्रोह-पूर्व युग के स्तर पर वापस पहुंच गए। हालांकि अमेरिका के साथ, उसे संबंधों को सामान्य बनाने में कुछ समय लगा क्योंकि अमेरिका ने कुछ हथियारों के वितरण को रोक दिया था तथा सेना को वार्षिक रक्षा सहायता भी रुकी हुई थी। यह केवल तभी प्रारंभ हुई जब सेना शासन ने लीबिया के साथ उसकी सीमा पर तथा सिनाई में आईएसआईएस के साथ संघर्ष करने की अपनी प्रतिबद्धता

प्रदर्शित की। मिश्र ने इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध अपने युद्ध में जीसीसी राष्ट्रों में कतर के अपवाद के साथ एक साझा मित्र ढूंढ लिया था, जिसने आगे चलकर इसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को भी बचाया।

मिश्र ने यूएई और सउदी अरब के पूर्ण सहयोग के साथ इस्लामवाद के विरुद्ध एक क्षेत्रीय और वैश्विक अभियान प्रारंभ किया, जिसने कुवैत के साथ, इसके राजकोष में लाखों डॉलर जमा कर लिए। राष्ट्रपति अल-सिसी तत्काल ही सउदी अरब के साथ शामिल हो गए जिसने स्वयं को ठगा महसूस किया था तथा अमेरिका द्वारा मुबारक को त्याग देने के उपरांत अमेरिकी नीति पर विश्वास खो दिया था[22] जीसीसी ब्लॉक में शामिल होकर, मिश्र ने इस्लामवाद से मुकाबला करने के लिए तुर्की-विरोधी सुन्नी धड़े का निर्माण करने का प्रयास किया। इसके अलावा, मिश्र और जीसीसी, दोनों ही की सैद्धांतिक और रणनीतिक सुभेद्यता ने उन्हें एक-दूसरे के निकट किया जहां दोनों ही एक ऐसी नीति का अनुसरण करते प्रतीत हुए जिसका उद्देश्य उनके संबंधित शासनों का बचाव करना था। दोनों ने लीबिया में समान पक्ष भी बनाए रखा तथा वहां शक्ति के समान धड़ों को समर्थन दिया। इसके अलावा, मिश्र ने रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को भी पुन: जवित किया ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके तथा दोनों ने अनेक करारों पर हस्ताक्षर किए जिनमें एक करार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और हथियारों के सौदे पर भी आधारित था। मिश्र ने सीरिया के मुद्दे पर रूस का पक्ष लिया जो, वस्तुत: जीसीसी का विरोधी था। इस पर पत्र में बाद में चर्चा की गई है।

इन अस्थिर परिस्थितियोंके भीतर जब प्रत्येक देश या तो अपने आंतरिक शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा था, अथवा दूसरे देशों के संघर्ष में भागीदार बन रहा था, एक राष्ट्र ऐसा था जिसने स्वयं को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त समय और स्थान वस्तुत: हासिल किया था और वह था - इजराइल।नि:संदेह, इजराइलघटनाओंके अकल्पनीयमोड़ लेने से हताश तथा पूरी तरह भौचक था, विशेषत: तब जब श्री मुबाकर लोगों के दबाव को झेल पाने में विफल रहे थे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इजराइल के लिए चिंता का प्रमुख विषय कैंप डेविड करार का भविष्य था, जो क्षेत्र में उसकी रणनीति का मुख्य बिंदु था क्योंकि वह सुभेद्य था और अवरोधक मानसिकता रखता था।[23] ट्यूनीशिया में घटनाक्रमों पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतनयाहू ने कहा था, "जिस भौगोलिक विस्तार में हम रह रहे हैं, वहां अस्थिरता का पर्याप्त विद्यमानता है। हमें आशा है कि स्थायित्व बहाल होगा।[24] उन्होंने भी इसे विद्रोह कहना उचित नहीं समझा तथा वे इसे एक उथल-पुथल कहने पर ही दृढ़ रहे। इजराइल की मुख्य चिंता उसके निकटतम पड़ोसियों जैसे जार्डन, सीरिया और मिश्र की प्रतिक्रिया, क्षेत्र में बढ़ती हुई असुरक्षा और अनिश्चितता तथा सिनाई और सीरिया के साथ लगी इसकी लंबी सीमाओं पर आईएसआईएस तथा अन्य जिहादी राज्य-विरोधी तत्वों की वृद्धि थी।

परंतु बहुत जल्द, ये चिंताएं और आशंकाएं तब समाप्त हो गई जब एक बार पुन: सेना ने सत्ता संभाल ली, जो इजराइल के लिए उसके हितों का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण रही थी। इस्लामी शक्ति के प्रति इजराइल और जीसीसी राष्ट्रों की साझी चिंता ने निकट भविष्य में दो धड़ों (जीसीसी और इजराइल) के बीच संबंधों को गहन बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। मिश्र में सेना की वापसी ने क्षेत्र में इजराइल की भू-रणनीतिक स्थिति को पहले के मुकाबले कहीं अधिक सुदृढ़ किया क्योंकि वे दोनों ही आतंक के विरुद्ध युद्ध में साझा हित रखते थे। मिश्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी की 10 जुलाई, 2016 की इजराइल यात्रा दशक में पहली यात्रा थी। दोनों मंत्रियों के बीच जेरूसलेम में बैठक हुई, जो इजराइल की स्व-घोषित राजधानी थी, जिसने, जैसा कि अर्धशासकीय समाचार पत्र, अल-अहराम, द्वारा सूचित किया गया था, अल-क्वड्स की कीमत पर जेरूसलेम के यहूदियों को मान्यता प्रदान की थी। सीरियाई मोर्चे पर युद्ध जितना अधिक समय चलता, उससे उसने ही सुरक्षित और शक्तिशाली इजराइल के उभरने की संभावना थी। जार्डन तथा अन्य पड़ोसी राज्य अपने स्वयं के विवादों में ही

उलझे हुए थे जो उन्हें फिलिस्तीन की समस्या से पीछे धकेल रहे थे, जो अब लगभग एक अनावश्यक मुद्दा बनकर रह गया था।

डब्ल्यूएएनए क्षेत्र में रूपांतरण का निर्धारण केवल प्रादेशिक कर्ताओं द्वारा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि वैश्विक कर्ताओं जैसे रूस और अमेरिका द्वारा भी किया जा रहा है जो समान रूप से क्षेत्रीय रणनीतिक विकास को परिभाषित और तैयार कर रहे हैं। भू-राजनीतिक पुनर्निर्धारण ने रूस और ईरान के बीच एक नए सहयोग को जन्म दिया है, तथा परिवर्तनकारी संबंध का एक जटिल जाल उभरने लगा है। सीरिया में निरंतर विद्यमान प्रतिद्वंद्विता ने क्षेत्रीय रूकावटों को बढ़ाया है तथा अब रूस और अमेरिका अल्प और दीर्घकालिक दोनों ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतिक रूप से कार्यवाही करते प्रतीत होते हैं। इस समय सीरिया क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के लिए समान रूप से भू-राजनीतिक केन्द्र बन गया है।

जहां तक क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप का संबंध है, अमेरिका के प्रत्युत्तर के प्रति पर्याप्त सतर्कता बरती गई है परंतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ओबामा ने क्षेत्र में अत्यंत हस्तक्षेप किए जाने के दस वर्षों से मुक्ति दिए जाने के वायदे के साथ पद पर अपना प्रथम कार्यकाल प्रारंभ किया जिसे उन्होंने 'आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध पर दिए गए अत्यधिक ध्यान' के रूप में वर्णित किया[25] परंतु बढ़ती हुई भंगुरता और शक्ति की कमी तथा आईएसआईएस के बाद में हुए उदय और उसकी सुदृढ़ता ने अमेरिका को वहां वापस ला दिया। विद्रोह के प्रारंभिक दिनों में, अमेरिका की भूमिका राष्ट्रपति असाद द्वारा शासन छोड़ जाने तथा मिश्र में सुचारू लोकतांत्रिक रूपांतरण की मांगों तक सीमित थी परंतु जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ती गई, अमेरिका ने सीरिया में विद्रोह बलों को प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया तथा बहुत ही जल्द, आईएसआईएस के विरुद्ध एक बड़ा अभियान आरंभ किया गया (प्रथम हवाई हमला और तत्पश्चात् जमीनी आक्रमण) यह पहले 2014 में इराक में और 2015 में सीरिया में छेड़ा गया था। अमेरिका ने आईएसआईएस के विरुद्ध अपने युद्ध में तुर्की और यूरोपीय शक्तियों की सहायता भी ली थी। ईरान ने भी कथित रूप से आईएसआईएस के विरुद्ध अपनी लड़ाई में अमेरिका का सशर्त अनुसमर्थन हासिल किया था। आतंक और आईएसआईएस के विरुद्ध युद्ध पर अमेरिका द्वारा दिया गया अत्यधिक बल उसे अरब प्रादेशिक व्यवस्था तैयार करने के लिए लोकतांत्रिक मुद्दे उठाने से वंचित कर सकता था। अरब विश्व में अमेरिकी नीति, विशेषत: इराक और सीरिया में, आतंकी नेटवर्कों को उखाड़ फेंकने की इसकी प्राथमिकता द्वारा अधिक प्रभावित है। परंतु इराक और सीरिया में, अमेरिका का पक्ष लीबिया के विपरीत अत्यंत रक्षात्मक है जहां उसे अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी थी। पूर्व में इराक और अफगानिस्तान के विपरीत, अमेरिका ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण को तरजीह दी तथा सीरिया और लीबिया, दोनों ही के मामलों को पहले संयुक्त राष्ट्र को सौंपा।

वर्तमान अरब संकट में जो बात वस्तुत: आश्चर्यजनक रही है, वह क्षेत्र से लगभग तीन माह की अनुपस्थिति के उपरांत रूस की रणनीतिक दृढ़ता है। जब रूस ने असाद के शासन के विरुद्ध चीन के साथ चार यूएनएससी संकल्पों को वीटो किया था, तो सबने यही सोचा था कि यह पश्चिमी धड़े के साथ रूस के मोहभंग की मात्र एक प्रतिक्रिया है, परंतु रूस को अरब विश्व के संपूर्ण घटनाक्रम को परिवर्तित करने का श्रेय दिया जा सकता है। केवल रूस के हस्तक्षेप के कारण ही प्रमुख संकट को टाला जा सका था जब सीरियाई शासन द्वारा नागरिकों के विरुद्ध रासायनिक हथियारों के प्रयोग के उपरांत असाद शासन के विरुद्ध अमेरिकी हवाई हमले किए जाने की प्रबल संभावना थी।

सीरिया में रूस का हस्तक्षेप रातों-रात हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से होनी तय की गई थी। सीरिया के मामले में इसकी रणनीति यथार्थवादी तथा विश्व राजनीति के पिछले दो दशकों

के अनुभवों पर आधारित थी।[26] रूस से चीन और ईरान से अभूतपूर्व स्तर पर सहयोग की मांग की तथा दोनों ही ने रणनीतिक, राजनीतिक और राजनयिक संदर्भ में भारी निवेश किया। रूस ने न केवल सीरियाई वार्ता को प्रोत्साहित किया ताकि पहल की अगुआई की जा सके बल्कि, सीरिया में सशस्त्र वाहनों, ड्रोनों, परिशुद्धता-चालित बमों और अन्य सैन्य उपकरणों के रूप में सीरिया को अपने सैन्य आपूर्तियों में वृद्धि कर[27] दी।

रूस ने सीरिया के रणनीतिक क्षेत्र में एक नई शक्तिशाली पहल की, जब उसने सितम्बर, 2015 में अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया और उसके बाद से यह क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है। इसने न केवल आईएसआईएस के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, बल्कि असाद के ढीले शासन से भी मुक्ति दिलाई। आज, सीरिया में इसकी दो-वर्षीय भागीदारी के उपरांत एक पूर्णत: संयुक्त रूस-सीरिया युद्ध विद्रोही बलों और आतंकी नेटवर्क के विरुद्ध छेड़ा जा रहा है, जिसमें आईएसआईएस भी शामिल है जिसकी जल्द ही समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

वर्तमान राजनीतिक विकास क्रम को जिस बात ने और अधिक प्रभावित किया है, वह बाहरी शक्तियों जैसे चीन, जापान, यूके, फ्रांस और कुछ हद तक इटली की बढ़ती भूमिका है। इन राष्ट्रों की भूमिका एक समान रही है तथा उनके मुख्य ध्यान की प्रकृति, जो उनके पूर्व संबंधों की प्रकृति है, रणनीतिक भागीदारी और आर्थिक एवं सुरक्षा हितों पर निर्भर करते हुए निरंतर बदलती रही है।

रूस, ईरान और चीन के मध्य एक साझा कारक (सीरिया में) पश्चिम की असमर्थता और इन देशों में पैठ बनाने के इसके उदारवादी विचार हैं। के व्यवस्था में परिवर्तन लाने के विरुद्ध हैं। लोकतंत्र, मानव अधिकार और अन्य उदारवादी विचारों के आधार पर पश्चिम से उत्पन्न होने वाला हस्तक्षेप इन तीन शासनों के समक्ष प्रश्न उत्पन्न करता है जो उन्हें उनके अपने देशों में असुविधाजनक बनाते हैं। वर्ष 2016 में चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग की सउदी अरब ईरान और मिश्र की प्रथम यात्रा को क्षेत्र में उसकी अपेक्षित नई भूमिका से पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। चीन ने हाल ही में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, जब वह इस क्षेत्र में आया था। ईरान के परमाणु सौदे को प्राप्त करने में चीन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है जिसने संभवत: चीन के लिए नए आयाम स्थापित करने का मार्ग खोल दिया है।

जब चीन ने सीरिया पर रूस के साथ दो यूएनएससी प्रस्तावों को वीटो किया था, तब क्षेत्रीय रणनीतिक क्रम में बदलाव के संबंध में चीन की बढ़ती भूमिका और रणनीतिक रुचि को देखा गया था। संयुक्त राष्ट्र के दूत श्री कोफी अन्नान द्वारा तैयार शांति योजना के पाठ में बड़े पैमाने पर आशोधन अधिरोपित करने में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका थी।[28] चीन ने सीरिया में रूसी पह लों को पर्याप्त सहयोग दिया और चीन के लिए यह मुख्य रूप से आर्थिक हित था जिसने सीरिया पर उसके रुख को निर्धारित किया। दमिश्क प्राचीन सिल्क रोड का पारंपरिक टर्मिनस नोड रहा है , जो यह संकेत करता है कि चीन अब सीरिया को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में देखता है। 'वन बेल्ट - वन रोड' की पहल चीन के लिए यह महत्वपूर्ण बनाती है कि सीरिया में स्थिति स्थिर बने।[29]

पूर्व के विपरीत, जापान ने भी इस उथल-पुथल के उपरांत अपनी रणनीतिक और राजनीतिक उपस्थिति को स्पष्टत: संवर्धित किया है। पूर्व में, इसकी नीति अति-सक्रिय शांतिवाद पर आधारित थी और इसके अलावा,

यह पश्चिमी सर्वसम्मति का अनुपालन करने की प्रकृति को स्पष्टत: परिलक्षित करती थी। परंतु अब निष्क्रियता से सक्रियता की ओर स्थानांतरण हुआ है जिसे, नि:संदेह ही ईरान के परमाणु सौदे में इसकी भूमिका तथा क्षेत्र में 9/11 के बाद अमेरिकी नीतियों के साथ इसके जुड़ाव से देखा जा सकता है। जापान क्षेत्र से हाइड्रोकार्बन का आयातक रहा है तथा इसने क्षेत्र से इसके कच्चे तेल के 90 प्रतिशत भाग का आयात किया[30] है और 2014 में, यह क्षेत्र से विश्व में तेल का बड़ा तेल आयातक रहा है [31] जिसे वहां पर इसकी नीति का निर्धारण करने में सहायता मिलती है।

जापान की प्राथमिक रुचि संभवत: इसकी व्यापक ऊर्जा क्षमता के कारण खाड़ी में विवाद के प्रसार में विपरीत सलाह प्रदान करना है। जापान ने, अपने घनिष्ठ मित्र-राष्ट्र अमेरिका के साथ इस उथल-पुथल के प्रारंभिक दिवसों में कह दिया था कि असाद ने अपनी वैधता खो दी है[32] और यह जापान द्वारा क्षेत्र में मामलों में सर्वाधिक स्पष्ट पक्षों में से संभवत: एक था। जून, 2012 में, इसने जापान में सीरियाई राजदूत को 'अग्राह्य व्यक्ति' घोषित कर दिया था। इसने पश्चिमी शक्तियों के साथ, कोफी अन्नान की योजना को समर्थन दिया तथा 'सीरिया के मित्र समूह' की मेजबानी की और 2012 में सीरियाई राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष को जापान आमंत्रित किया।[33] परंतु बाद में, इसने अपना ध्यान मानवीय सहायता पर केन्द्रित कर दिया और इसका पक्ष सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र के वर्णन पर अधिक आधारित था। जापान ने आतंरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए अनेक बार वित्तीय सहायता प्रदान की और उनकी मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र और अनेक एनजीओ के साथ समन्वय किया। यह उन कुछेक राष्ट्रों में से एक है जिसने सीरिया के रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए सौदे की मध्यस्थता की।[34] जापान ने स्वायत्तता के कुछ संकेत प्रदर्शित किए जब इसने सीरिया में अमेरिकी नेतृत्व की सैन्य कार्यवाहियों का समर्थन नहीं किया।

क्षेत्र में संकट द्वारा जापान और चीन के बीच विरोधात्मक समीकरण उत्पन्न होने की संभावना है, अत: वहां पर शामिल होने के उनके तरीके भी भिन्न-भिन्न हैं।[35] जापान अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक मामलों में वृहद् भूमिका पाने का आकांक्षी भी है। वर्ष 2013 में इस क्षेत्र के अपने दौरे (सऊदी अरब, यूएई, तुर्की) के दौरान,[36] जापान के प्रधानमंत्री श्री आबे ने यह घोषणा की थी कि इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग स्थापित करना है तथा एक ऐसा बहु-आयामी संबंधी बनाना है जिसमें राजनीति और सुरक्षा तथा संस्कृति भी शामिल हो।[37]

यूके और फ्रांस, दोनों ही क्षेत्रीय संकट के संदर्भ में अपने पक्ष के प्रति पर्याप्त स्पष्ट और दृढ़ रहे हैं। सीरिया में, दोनों ही ने राष्ट्रपति असाद के हटने की मांग की तथा अमेरिका के साथ, उन्होंने न केवल विद्रोही बलों का पक्ष लिया बल्कि शासन का सामना करने के लिए विद्रोही बलों को हथियार और अति-आधुनिक दूरसंचार प्रणाली भी प्रदान की।[38] अमेरिका के पश्चात् ब्रिटेन और फ्रांस, अगस्त, 2013 में नागरिकों के विरुद्ध रासायनिक हथियारों के कथित प्रयोग के उपरांत सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप करने की धमकी देने वाले प्रथम राष्ट्र थे। यूके ने इस संबंध में यूएनएससी में एक सुझावी संकल्प भी प्रस्तुत किया था। फ्रांस और यूके ने असाद सरकार के

विरुद्ध यूएनएससी में अनेक संकल्प पेश किए और उनका सह-प्रायोजन किया जिनमें रूस के नेतृत्व वाले हवाई हमलों को समाप्त करने के लिए एलेप्पो पर संकल्प भी शामिल था। [39] दोनों ही सीरिया और इराक में आईएसआईएस के विरुद्ध युद्ध में गठबंधन का भाग भी रहे थे।

इसी प्रकार, लीबिया में, दोनों देशों ने शासन विरोधी समूहों का खुलकर समर्थन किया तथा दोनों ही लीबिया में नाटो मिशन के अग्रेता थे। सीरिया में गृह-युद्ध फैलने के उपरांत, दोनों राष्ट्रों ने एक अभियान छेड़ा तथा वे कर्नल गद्दाफी के विरुद्ध यूएनएससी संकल्प के मुख्य समर्थक बन गए। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री कैमरून ने 28 फरवरी, 2011 को अपने रक्षा सचिव को 'नो फ्लाई जोन' के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया था, जो इस संबंध में पारित किए गए यूएनएससी के संकल्प से काफी पहले की बात है।[40] फ्रांसीसी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री गद्दाफी की मृत्यु के उपरांत लीबिया की यात्रा करने वाले प्रथम नेता थे। ब्रिटिश सरकार गद्दाफी के उपरांत लीबिया में अधिक रुचि ले रही थी तथा उन्होंने एनटीसी सेना को प्रशिक्षण देने तथा गंभीर रूप से बीमार लीबिया वासियों को यूके में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का वचन दिया।[41] जहां तक यमन का संबंध है, ब्रिटिश सरकार ने लगातार राजनीतिक समाधान का आह्वान किया है तथा अमेरिकी राजदूत के प्रयासों को सहायता प्रदान की है। अपने अमेरिकी, सउदी अरब और यूएई समकक्ष नेताओं के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेस में, ब्रिटिश विदेश सचिव बोरिस जॉनसन ने हाल ही में कहा कि जीसीसी की राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय वार्ता के परिणाम और यूएनएससी संकल्प का केवल यही अर्थ है कि यमन में संकट का समाधान किया जाए।[42]

फ्रांस और यूके की तुलना में, इटली की भूमिका अत्यंत अपरिपक्व रही है। इटली ने लीबिया के विरुद्ध नाटो के नेतृत्व वाले अभियान का विरोध किया तथा इसके पूर्व राष्ट्रपति बेर्लुसकोनी ने कहा था कि नाटो ने ऐसे नेता की हत्या की है जिसे लोग प्रेम करते थे।[43] लीबिया में नाटो की संलिप्तता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इटली ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस-विरोधी(इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया) युद्ध में शामिल होने से इंकार कर दिया था परंतु उसकी विशेष सेनाओं ने लीबिया के शहरों में आईएसआईएस से संघर्ष करने के लिए कथित रूप से ब्रिटिश सेनाओं का साथ दिया था। इटली ने भी अमेरिकी सेनाओं को सिसली में अपने हवाई ठिकाने का प्रयोग करने की अनुमति दी थी।

यह सिद्ध हो चुका है कि चूंकि देश में केन्द्रीय प्राधिकारी पीछे हट गए थे, अत: राज्य-विरोधी तत्वों की भूमिका अधिक प्रधान हो गई थी तथा यही आज अरब विश्व में भी हो रहा है। पिछले पांच-छह वर्षों में, क्षेत्र के प्रत्येक देश ने राज्य-विरोधी तत्वों की प्रधानता में अभूतपूर्व स्तर पर हुई वृद्धि को देखा है। अनेक आतंकी और कट्टरवादी संगठनों में वृद्धि ने राज्य को न केवल शक्तिहीन बनाया है, बल्कि वे इराक, सीरिया और लीबिया में समांतर राजनीतिक एजेंसियां भी बन गए हैं। लेबनान में आईएसआईएस, हेजबुल्ला, सीरिया में जबात अल-नुसरा तथा अन्य कट्टरवादी मोर्चे, इराक में सैडरिस्ट, यमन में हौथी तथा लीबिया में ऐसे ही समूहों ने राज्यों को उनके तानाशाहों के हाथों में बंदी बना लिया है। इराक में जून, 2014 में आईएसआईएस के उदय ने मलीकी

के शासन की नीव को लगभग हिला दिया था तथा इराक और सीरिया में आईएसआईएस द्वारा बड़े भू-भागों पर किया गया नियंत्रण जब गुप्त नहीं रहा है।

कुछ मामलों में, ये जेहादी क्षेत्रीय शक्तियों के सहयोगी अथवा अनुयायी हैं, जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उनका पालन-पोषण कर रहे हैं। उनका उदय और उनकी मजबूती अतीत ओर वर्तमान के घरेलू और क्षेत्रीय राजनीतिक संदर्भ में भी अवस्थित है। वर्तमान क्षेत्रीय परिदृय में, राज्य-विरोधी तत्वों की भूमिका ने स्वयं राज्य की भूमिका को न्यून बनाया है। यह बात कतर के मामले में स्पष्ट है जो इसके राज्य-विरोधी तत्वों के माध्यम से शक्तिशाली देशों जैसे इजराइल और तुर्की की तुलना में लीबिया में परिवर्तन लाने में अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार, हिजबुल्ला की भूमिका को भी कम नहीं आंका जा सकता है। समान रूप से, नृजातीय, जनजातीय और पंथवादी संगठनों के रूप में राज्य-विरोधी तत्वों ने यमन ओर लीबिया में अनेक प्रादेशिक और वैश्विक शांति की अनेक पहलों को विफल किया है।

वर्तमान जटिलताएं और उभरते परिदृश्य

जिन बातों ने क्षेत्र में पिछले छह वर्षों की उथल-पुथल को वस्तुत: प्रभावित किया है, वे हैं - हितधारकों और प्राक्सियों के मध्य रणनीतिक, राजनयिक और राजनीतिक तालमेल का अभाव, गठबंधन तथा विरोध-गठबंधनों का निर्माण, अंतरा और अंतसैद्धांतिक और पंथवादी युद्ध तथा विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक कारकों के मध्य पारस्परिक संबंधों का रूपांतरित होता ताना-बाना। क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य अत्यंत जटिल है तथा रेखांकित की गई जटिलता विवाद को लंबा खींचने और पंथवादी मतभेद को गहरा बनाने की समस्त क्षमताएं रखती है जिसमें और अधिक कर्ताओं की भागीदारी भी संभव है।

रणनीतिक गैर-निरंतरता मिश्र के रूस की ओर किए गए हालिया रूपांतरण के अलावा कहीं और अधिक सुस्पष्ट नहीं है, जब यूएनएससी में, मिश्र ने सीरियाई संकट पर रूस के साथ दो बार वीटो किया, जो सउदी अरब के पक्ष में प्रतिकूल था।[45] यमन में वर्तमान युद्ध के बारे में मिश्र की इस उभयमुखी स्थिति ने दोनों के बीच दरार भी पैदा कर दी है तथा सीरिया के बारे में मिश्र की स्थिति सउदी अरब की तुलना में रूस और ईरान के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण है। ये सभी घटनाक्रम घटित हो रहे थे जब 2014 के चुनावों में, राष्ट्रपति एल-सिसी ने स्वयं यह प्रतिज्ञा ली थी कि खाड़ी राष्ट्रों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप मिश्र की सेना के सिद्धांतों का एक भाग होगा।[46]

जो बात अधिक आश्चर्यजनक थी, वह जीसीसी के विरुद्ध मिश्र की ओर से पाला बदलना था, जिसने इसे उसके आर्थिक संकट से लगभग बाहर निकाल दिया था। इसके जवाब में, सउदी अरब ने इसे अक्तूबर के लिए तेल की आपूर्ति नहीं भेजी, जो दोनों पक्षों के बीच 22 बिलियन यूएस डॉलर का भाग था जिसे द्वारा इसने पांच वर्ष के लिए प्रत्येक माह 700,000 मिलियन टन परिष्कृत तेल का निर्यात करने का वायदा किया[47] इस संबंध में भी सूचनाएं प्राप्त हुई थीं मिश्र ने तेल समृद्ध देशों के साथ अपने संबंधों में कड़ुवाहट आने की प्रत्याशा में अपने मंत्री को ईरान भेजा था, जो सउदी अरब का कड़ा प्रतिद्वंद्वी था, ताकि एक नया तेल सौदा निष्पादित किया जाए जो क्षेत्रीय राजनीति में एक सहायक सिद्ध हो सके।

सीरिया में स्थिति और भी अधिक जटिल रही है जहां किसी ने भी कभी भी राष्ट्रपति असाद की निर्वासन योजना अथवा किसी राजनीतिक रूपांतरण के बारे में कुछ नहीं सुना था। आज जो हम सीरिया के बारे में सुन रहे हैं, वह केवल आईएसआईएस, आईएसआईएस-विरोधी तथा असाद-विरोधी विद्रोही बलों के बीच हुई

भयंकर लड़ाई, संयुक्त रूस-सीरियाई हवाई हमलों तथा अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन देशों के हवाई हमलों के बारे में ही है। असाद-विरोधी बलों, जैसे सउदी अरब, तुर्की, यूएई और कतर के पूर्व-समर्थकों की आवाजें रूस द्वारा सितम्बर, 2015 में सीरिया की ओर से युद्ध में शामिल होने के पश्चात् बंद हो गईं। आज, सीरिया मानवाधिकार उल्लंघन के संदर्भ में एक अत्यंत निष्कृष्ट परिदृश्य में शामिल हो गया है, जहां देश का एक बड़ा भाग या तो कब्जे में है अथवा किसी संघर्ष का सामना कर रहा है तथा लोगों के मारे जाने की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

यमन में युद्ध एक कभी न समाप्त होने वाला युद्ध बन गया। सउदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन का दो वर्ष लंबा संघर्ष किसी रणनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति करने में विफल रहा। विद्रोही हौथी बल अभी भी एक विशाल भू-भाग पर नियंत्रण बनाए हुए हैं तथा वे सउदी अरब के विरुद्ध एक आड़ के रूप में कार्य कर रहे हैं। निर्वासन में रह रहे हादी मंसूर का शासन स्थिर राजनीतिक रूपांतरण की ओर कोई भी कदम बढ़ाने में विफल रहा है। कुवैत में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में संचालित अनेक शांति पहलें, क्षेत्रीय पहलें तथा ओमान द्वारा गुप्त रूप से संचालित राजनयिकता अतीत में राजनीतिक प्रक्रिया को पुन: बहाल करने में विफल रही है क्योंकि यमन की दलदलनुमा परिस्थिति में अनेक घरेलू और क्षेत्रीय हितधारकों का निरंतर हस्तक्षेप रहा है।

लीबिया भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार की स्थापना के बावजूद समान प्रतिकूल परिदृश्य प्रस्तुत करता है। परंतु आज, यह राजनीतिक धड़ों के भीतर अनेक युद्धरत समूहों और अन्य इस्लामी कट्टरवादी संगठनों और मुख्य रूप से आईएसआईएस के भारी दबाव के अंतर्गत गुजर रहा है जिनका दबदबा अभी भी देश के अधिकांश शहरों पर कायम है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुर्की रूसी विमान को लक्ष्य बनाकर गिराने की पृष्ठभूमि में लगभग एक वर्ष के कटु संबंधों के उपरांत रूस के साथ अपने संबंधों में सुधार करने में समर्थ रहा है। यह मारमारा घटना के बाद लगभग पांच वर्षों के अलगाव के पश्चात् इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध पुन: बहाल करने में भी सफल रहा है। अभी भी तुर्की क्षेत्र में हाशिए पर रखी गई शक्ति ही प्रतीत होता है क्योंकि कुर्दिश मामले पर इसके विभिन्न राष्ट्रों जैसे सीरिया और इराक के साथ मतभेदों में वृद्धि हो रही है।

वर्तमान में, मोसुल में आईएसआईएस के विरुद्ध इराक की चल रही लड़ाई में कोई योगदन दिए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि इराक सरकार ने इसे अपनी सेनाओं को वापस लेने के लिए कहा है, जबकि अमेरिकी-नेतृत्व की सेनाएं, इराक की सेना, कुर्दिश पेशमेर्गा और ईरान की शिया मिलिशिया परस्पर समन्वय बनाए हुए हैं। इस घटनाक्रम में तुर्की की भूमिका लगभग अस्पष्ट है। वर्तमान युद्ध ने क्षेत्र में ईरान की स्थिति को और मजबूत बनाया है, जो आगे रणनीतिक समझौते करने के अवसर बनाने के लिए इसकी सहायता कर रही है।

इराक के कुर्दिश क्षेत्र में तुर्की की सेना की उपस्थिति की इराकी प्रधानमंत्री द्वारा भारी आलोचना की गई है जिन्होंने इसे इराकी संप्रभुत्ता के उल्लंघन की संज्ञा दी है। इराक मोसुल में वर्तमान आईएसआईएस-विरोधी युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है। तुर्की, जिसकी नाटो में दूसरी विशालतम सेना है, पेशमेर्गा और सुन्नी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए इराक के उत्तरी भाग में तैनात है[48]। क्षेत्र में तुर्की के पक्ष को जिस बात ने और कमजोर बनाया है, वह जुलाई, 2016 में राष्ट्रपति एर्डोगन के विरुद्ध किया गया विद्रोह का प्रयास है, जिसने फिलहाल तुर्की को क्षेत्रीय क्षमता प्रदर्शित करने से रोक दिया है। कथित रणनीति-निर्माताओं और उनके सहयोगियों के विरुद्ध बाद में की गई कार्यवाही ने पुन: देश को वैश्विक निगरानी के अंतर्गत ला खड़ा किया है तथा यह संभावना है कि तुर्की को आने वाले समय में समस्याओं का सामना करना होगा।

अरब विश्व में संभावित भावी परिदृश्य

क्षेत्र में पिछले छह वर्षों के दौरान आए उतार-चढ़ावों के उपरोक्त वर्णन के आलोक में, पत्र का आगामी और अंतिम खंड उन कुछ संभावित भावी परिदृश्यों का वर्णन करेगा जिनका सामना अरब विश्व द्वारा किया जा सकता है। ये परिदृश्य वर्तमान घटनाओं के ही परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए है, जो शक्ति के संतुलन रणनीतिक संधि और विरोधी गठबंधन के संदर्भ में इस अति सतर्क क्षेत्र की भू-राजनीति को प्रत्यक्षत: प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय व्यवस्था के शीर्ष पर स्वयं को स्थापित करने के लिए प्रमुख देशों द्वारा की जाने वाली प्रतिस्पर्धा भी इसका एक कारक है। सबसे पहले यह खंड कुछ प्रधान देशों का अलग-अलग वर्णन करेगा तथा उसके उपरांत समग्र क्षेत्र का एक संक्षिप्त खांचा प्रस्तुत किया जाएगा।

ईरान : क्षेत्रीय विभाजन तथा प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा अरब राजनीति की एक दीर्घकालिक विशेषता रही है। परंतु जो बात अरब विद्रोह के बाद वाले चरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वह इराक में सद्दाम के प्रस्थान के उपरांत देखी गई उदासीनता के पश्चात् ईरान और सउदी अरब के बीच प्रतिद्वंद्विता के एक नए स्वरूप का उभरना[49] है। ईरान एकमात्र ऐसा देश है, जो निकट भविष्य में क्षेत्र के भावी मार्ग पर अधिपत्य जमा सकता है। यह अरब अस्त-व्यस्तता के बाद रणनीतिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावशाली देश के रूप में उभरा है। इसके सीरिया पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेने की संभावना है तथा यह निकट भविष्य में इराक पर समस्त रणनीतिक प्रभावों को अधिरोपित करेगा। सउदी अरब और तुर्की को लगभग पछाड़ कर ईरान, अत्यंत शक्तिशाली बनकर उभरा है जो सीरियाई मामलों में हस्तक्षेप करने वाली दो पूर्व-शक्तियां थी और आज, ईरान रूस के रणनीतिक समीकरण में एक सुविधाजनक स्थान रखता है, जिसकी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है।

ईरान के पास इराक, यमन, लेबनान और सीरिया के विद्युत निर्वात की पूर्ति करने की पूर्ण क्षमता विद्यमान है। ईरान लेबनान, फिलीस्तीन, मिश्र और इराक में राजनीति पर प्रधानता जमाने के लिए एमबीएच, हिजबुल्ला, हमास और अल-कड्स ब्रिगेड तथा ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स(आईआरजीसी) का प्रयोग कर सकता है। मिश्र के साथ द्विपक्षीय स्तर पर, जिसमें कुछ अधिक होने की संभावना नहीं है तथा यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सउदी-मिश्र संबंधी किस प्रकार कार्य करेगा, बहरीन भविष्य में एक अन्य सहयोगी देश हो सकता है क्योकि यह अभी भी ईरान के लिए एक खुले घाव की भांति है जो पुन: दृढ़ निश्चय कर सकता है और बहरीन को जीसीसी के सर्वाधिक नाजुक भाग में बदल सकता है। न केवल जीसीसी, बल्कि जॉर्डन और मिश्र जैसे राष्ट्र भी ईरान के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित होंगे। जॉर्डन के सम्राट ने पहले ही क्षेत्र में सद्दाम के उपरांत काल को शियाओं की सुदृढ़ता के लिए एक नए निर्माण की संज्ञा दी है[50]।

बढ़ती प्रतिद्वंद्विता तथा पंथवादी और सैद्धांतिक राजनीति में तत्पश्चात् हुई संवृद्धि द्वारा संपूर्ण खाड़ी क्षेत्र की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता तथा सुरक्षा पर एक प्रत्यक्ष चुनौती प्रस्तुत करने की संभावना है। त्रुटिपूर्ण व्यवहार तथा क्षेत्र के मध्य गहन मतभेद स्वाभाविक रूप से बाहरी क्षेत्रीय और वैश्विक कारकों को अधिकारिक रणनीतिक गहनता प्रदान करेंगे। यह विभाजन राज्य-विरोधी कर्ताओं को और सुदृढ़ बनाएगा जो न केवल क्षेत्र में राजनीति के मार्ग का निर्धारण करने के लिए बल्कि क्षेत्र में स्थायित्व के संवर्धन के विपरीत एजेंडा अधिरोपित करने के लिए क्षेत्रभर से राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक सहयोग प्राप्त करेंगे।

विद्यमान राजनीतिक और रणनीतिक परिदृश्य क्षेत्र के लिए अनुकूल नहीं है तथा इस संकट के शीघ्र समाधान के लिए तुलनात्मक रूप से कम आशा ही दिखाई पड़ती है। इसका श्रेय संकट की जटिलता, अनेक देशों और विभिन्न हितधारकों की संलिप्तता तथा समूचे क्षेत्र में नए त्रुटिपूर्ण विचारों के उत्पन्न होने को दिया जा

सकता है। वर्तमान उथल-पुथल और अस्थिरता शस्त्रीकरण के लिए नई होड़ आरंभ किए जाने की संभावना में वृद्धि कर सकती है तथा जीसीसी अपने रक्षा बजट को बढ़ा सकता है तथा एक उच्च स्तरीय पंथवादी युद्ध में शामिल हो सकता है और आडम्बर की लड़ाई में फंस सकता है। सउदी अरब पहले ही अमेरिका और चीन के उपरांत रक्षा पर व्यय करने वाला तीसरा विशालतम देश है, क्योंकि इसने अपने कुल बजट में से पच्चीस प्रतिशत भाग पहले ही केवल रक्षा पर ही व्यय कर दिया है।[51] इस बात की संभावना है कि क्षेत्र ईरान और जीसीसी के बीच घोषित, अघोषित, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष झड़पों के विभिन्न स्तरों को देखेगा और संभवत: यह स्थिति विगत दशकों में मिश्र, ईरान और जार्डन की क्षयपूर्ण भूमिका के फलस्वरूप और भी स्पष्टत: दिखाई देगी। क्षेत्र में ईरान जितनी अधिक रणनीतिक गहनता हासिल करता जाएगा, हिजबुल्ला और ईरानी मिलिशिया जैसे और अधिक संगठन सुदृढ़ होते जाएंगे। ईरान के संरक्षण प्राप्त हिजबुल्ला ने पहले ही सीरिया में गृह युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका के कारण मजबूत और सुदृढ़ता हासिल कर ली है। ईरान ने विभिन्न तरीकों से क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप किया है: राज्य-विरोधी तत्वों का सृजन करके, पंथवादी नीति का संचालन करके तथा अमेरिका और इजराइल विरोधी भावनाओं को भड़काकर।[52]

क्षेत्र में ईरान का घोर प्रतिद्वंद्वी सउदी अरब, जिसने हाल में बहु-आयामी आर्थिक और राजनीतिक सुधार प्रारंभ किए हैं (सउदी अरब खंड में इन विवरणों पर चर्चा की गई है), नि:संदेह ही निकट भविष्य में इसके वर्तमान रणनीतिक दाव को प्रभावित करेगा। परंतु, फिलहाल, यह वर्तमान रूपांतरित होती प्रादेशिक व्यवस्था में एक प्रमुख पराजित देश ही प्रतीत होता है। सउदी अरब के भी इराक, सीरिया और यमन में इसे स्पष्टत: हाशिए पर रखे जाने को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति में और गिरावट आने की संभावना है, जहां इसकी ईरान-समर्थित हौथियों के साथ युद्ध ने कोई अनुकूल परिणाम प्रदर्शित नहीं किए हैं। सद्दाम का निष्कासन, बाथ पार्टी के प्रभाव की समाप्ति तथा उसके उपरांत शक्ति के निर्वात ने ईरान के लिए एक सुनहरा अवसर परोसा है। सीरिया में ऐसा प्रतीत होता है कि सउदी शासन ने अपना प्रभाव खो दिया है क्योंकि अब वहां राष्ट्रपति असाद को हटाने की मांग सुनाई नहीं देती, जो एक समय पर सउदी अरब और क्षेत्र में उसके सहयोगियों की मुख्य मांग थी। असाद को शासन में बनाए रखना ईरान की एक सबसे बड़ी रणनीतिक और सैद्धांतिक विजय है तथा इसने ईरान को क्षेत्र में सउदी अरब पर एक अभूतपूर्व स्तर तक महत्व प्रदान किया है। असाद का निष्कासन ईरान के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक धक्का होगा क्योंकि यह इसे हमास और हजबुल्ला को अंतरित करने के लिए ईरान के रणनीतिक प्रतिस्पर्धी के विरुद्ध एक बचाव की भांति है जो ईरान के लिए एक सैद्धांतिक आवश्यकता है।

ईरान एक सुधारवादी शक्ति के रूप में उभरा है तथा यह क्षेत्र के भू-राजनीतिक नियंत्रण को परिवर्तित करने की पर्याप्त क्षमता रखता है और वह ईरान से लेकर भूमध्य सागर तक के क्षेत्र में अपना स्थायी नियंत्रण चाहता है। ईरान क्षेत्र के मामलों के लिए अपनी जनसांख्यिकी, पश्चिम के साथ परमाणु सौदे के दृष्टिगत नई अर्जित की गई आर्थिक शक्ति और रूस और पश्चिमी शक्तियों के साथ इसके अनेक हथियार सौदों के कारण संवर्धित सैन्य क्षमता के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ईरान क्षेत्र में घटने वाले घटनाक्रमों पर अपनी आज्ञा की मुहर लगाना चाहता है तथा दिन-प्रति-दिन के घटनाक्रमों ने इसके रणनीतिक समीकरण के संदर्भ में ईरान के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं। सउदी अरब की रणनीति यमन में भी अलग-थलग पड़ रही है (इसके प्रचालन ने सना को वापस लेने में सफलता नहीं पाई है अथवा सउदी भूभाग पर उसकी मिसाइलों के हमलों को नहीं रोका है) जहां ईरान ने अंतिम स्तंभ को सुरक्षित करने के सउदी डिजाइन को निष्फल कर दिया है तथा हौथी किसी भी सूरत में पराजित होते नहीं दिख रहे हैं।

क्षेत्र में ईरान के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका और यूके द्वारा नज़रअंदाज नहीं किया गया है तथा दोनों ही ने ईरान के बढ़ते हुए हस्तक्षेप के विरुद्ध पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। नई ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने सउदी अरब के अपने हालिया दौरे में तथा जीसीसी शिखर-सम्मेलन में दिए गए संबोधन में ईरान के बढ़ते हुए हस्तक्षेप पर गहरी चिंता व्यक्त की है तथा ईरान को क्षेत्र के लिए संकट बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि "खाड़ी के सुरक्षा हमारी सुरक्षा है तथा 'आपकी (खाड़ी की) समृद्धि हमारी (यूके की) समृद्धि है।'[53] जीसीसी ईरान की नई राजनीतिक अभिलाषा और रणनीति से उत्पन्न होने वाली बाह्य चुनौती का सामना करने के लिए अन्य सहयोगियों से नई प्रतिबद्धता हासिल कर रहा है जो यह क्षेत्र में मौजूदा उथल-पुथल के मध्य संचालित कर रहा है। इस दौरान, अमेरिका ने क्षेत्र में नए स्तर के ईरानी हस्तक्षेप के विरुद्ध ईरान को निरंतर चेतावनी दी है और हाल ही में ही, इसके नए रक्षा सचिव श्री जेम्स मैटिस ने ईरान को 'विश्व के विशालतम आतंकवाद-प्रायोजक' की संज्ञा दी है। सउदी की अधिकारिक न्यूज एजेंसी के अनुसार मोहम्मद-बिन-सुलेमान, डिप्टी काउन प्रिंस तथा सउदी अरब के रक्षा मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्षी श्री जेम्स मैटिस के साथ 1 फरवरी, 2017 को टेलीफोन द्वारा बात की तथा दोनों ही ने जीसीसी क्षेत्र में ईरान तथा इसके सहयोगियों के हस्तक्षेप की भर्त्सना की।[54]

परमाणु ससौदे के उपरांत वैश्विक क्षेत्र में ईरान का पृथक्करण तुलनात्मक रूप से कम हुआ है तथा अरब उथल-पुथल इसके लिए एक नया अवसर लेकर आया है कि यह अपनी भूमिका को पुन: परिभाषित करे तथा उस महत्व को हासिल करे, जो इसने पिछले तीन दशकों में खो दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ईरान अनेक आंतरिक राजनीतिक विरोधाभासों से घिरा हुआ है, परंतु इसके क्षेत्र में इसके द्वारा नई रणनीतिक और राजनीतिक गहनता अर्जित करने तथा इसकी अपनी रणनीतिक आकांक्षाओं के अनुसार क्षेत्र का स्वरूप निर्धारित करने की राह में बाधा बनने की संभावना नहीं है। वैश्विक समुदाय का पूर्व नवीकरण अब ईरान के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा है, जो परमाणु सौदे से पहले का मुद्दा था। परमाणु सौदे ने ईरान को दृष्टिकोण की नई स्वतंत्रता प्रदान की है। ईरान क्षेत्र में शक्ति निर्वात को भरेगा तथा इसकी सूचना इसकी पंथवादी और सैद्धांतिक अपील द्वारा दी जाएगी। अब, ईरान के प्रभाव को सीमित करने के लिए कोई नियंत्रण दिखाई नहीं देता है तथा क्षेत्र में व्यापार को नियंत्रित करना ईरान के लिए विशेषज्ञ लाभ की बात होगी। क्षेत्र में आज जो कुछ घट रहा है, वह उसके हितों सैद्धांतिक मूल्यों तथा क्षेत्र में उसके हितों के अनुकूल है।

क्षेत्र निकट भविष्य में ईरान और रूस के बीच नए प्रकार की प्रतिद्वंद्विता और रणनीतिक गुटबंदी को देख सकता है, जिसकी दूसरी ओर जीसीसी और पश्चिमी शक्तियां, विशेष रूप से यूके और अमेरिका होंगे। यूके की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने जीसीसी के बीच गहन संबंधों की भावी संभावना के बारे में पहले ही संकेत दे दिया है, जो ईरान के उदय के प्रतिकूल कार्य करेगा। रूस के साथ मिलकर ईरान द्वारा तुर्की के विकल्प को सीमित किए जाने की संभावना है, जिसकी क्षेत्र में अपनी आकांक्षाएं हैं। ईरान क्षेत्र के बाहर भी अधिकाधिक संधियां करने के अवसर तलाश रहा है जैसा कि इसके रूस के साथ गठबंधन से स्पष्ट है तथा इसने लातिन अमेरिका देशों के साथ भी पहले ही संबंध स्थापित कर लिए हैं। ईरान-रूस संबंध मध्य एशिया में अनेक राष्ट्रों जैसे अजरबैजान की स्वायत्तता को चुनौती दे रहे हैं जहां दोनों ने ही करार किया है। रूस और ईरान दक्षिणी कांकेशस क्षेत्र में आर्थिक अतिक्रमण भी कर रहे हैं। क्षेत्र का एक व्यापक अवलोकन करने पर यह दिखाई देता है कि ईरान के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक संबंध ईरानी सुदृढ़ता के स्तर का निर्धारण करेंगे।

इजराइल : इजराइल अरब उथल-पुथल के उपरांत वस्तुत: सुदृढ़ रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है तथा इसके ऐसे ही बने रहने की संभावना है। ऐसा होने का एक प्राथमिक कारण अरब की अस्त-व्यस्तता के दृष्टिगत क्षेत्रीय

प्राथमिकता में पूर्णत: परिवर्तन होना है तथा इजराइल की ओर ध्यान न दिया जाना ही इजराइल के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। पिछले पांच वर्षों में, जब क्षेत्र उथल-पुथल से गुजर रहा था और वैश्विक शांति प्रयास सीरिया, यमन, इराक और लीबिया पर ही केन्द्रित थे; इजराइल सरकार ने उपनिवेश विस्तार की अपनी अति आलोचनात्मक नीति को जारी रखा। यह निर्धारित करना गलत नहीं था कि 'कोई वार्ता नहीं' इजराइल के लिए श्रेष्ठ वार्ता है तथा फिलिस्तीन- इजराइल संकट पर किसी कृत्रिकता के अभाव के निकट भविष्य में भी मामले के रूप में बने रहने की संभावना है। क्षेत्र में विद्यमान व्यापक अशांति इजराइल की ओर से ध्यान हटाएगी।

इजराइल की सीरिया और मिश्र के साथ लगी सीमा, जो इजराइल के अस्तित्व की जीवन-रेखा है, मिश्र में सेना की वापसी तथा सीरिया में हिजबुल्ला(इजराइलके लिए एक अन्य संकट निर्माता) और अन्य सेनाओं की संलिप्तता के कारण आज के समय में सबसे सुरक्षित सीमा है। यथास्थिति बहाल रहना ही इजराइल के लिए निकट भविष्य में श्रेष्ठ विकल्प है। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि इजराइल को सीरिया द्वारा हमास को हथियारों की आपूर्ति से कोई खतरा उत्पन्न होगा, जैसाकि पूर्व में हुआ था, क्योंकि दोनों वर्तमान और नए शासन आंतरिक पुनर्निर्माण पर ही ध्यान केन्द्रित करेंगे। इजराइल सीरिया में किसी अज्ञात शत्रु के स्थान पर किसी अज्ञात शत्रु की उत्तरजीविता को तरजीह देगा। सीरिया द्वारा इजराइल के विरुद्ध किसी प्रकार की सैन्य कार्यवाही करना संभव नही है तथा गोलन हाइट्स पर भी कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि शासन ने अपनी वैधता खो दी है। क्षेत्र में तेजी से परिवर्तित होते रणनीतिक और राजनयिक परिदृश्य में, हमें आश्चर्य नहीं होगा यदि अरब विश्व में अधिक-से-अधिक राष्ट्र इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर लेंगे जैसा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतनयाहू ने स्वयं यूएनजीए की पिछली बैठक में दावा किया है कि इजराइल राज्य के विरुद्ध अरब नेतृत्व के दृष्टिकोणों में तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है[5]।

क्षेत्र में अधिकांश सरकारें संकट के लंबा खिंच जाने से थकान महसूस कर रही है तथा, बहुत जल्द, कतर और ओमान इजराइल राज्य को मान्यता प्रदान कर देंगे। हालांकि वे व्यापार और सेना के साथ बात प्रारंभ करेंगे। सउदी अरब अपने वित्तीय संकटों की वजह से अब फिलिस्तीन को समर्थन जारी रखने की स्थिति में नहीं है। ईरान परमाणु सौदे के पश्चात् अरब नेता भड़क गए हैं तथा इस सौदे को रद्द करने के लिए जीसीसी नेताओं और इजराइल के बीच गुप्त राजनयिकता की खबरें मिल रही हैं। इसके अलावा, चालू विवाद ने अरब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आंतरिक और बाह्य पलायन को कारित किया है, जिसका अतिरिक्त लाभ इजराइल को उसके राष्ट्रीय सुरक्षा वर्णन के संबंध में मिलने की संभावना है, जो क्षेत्र में उसकी रणनीति की विशेषता है। मिश्र में इस्लामवाद की समाप्ति ने इजराइल के लिए लोकतांत्रिक साख हासिल की है, जिसने सदैव ही दावा किया है कि यह राजतंत्र और तानाशाही के द्वीप में एकमात्र लोकतंत्र है। अरब लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का पूर्णत: ह्रास, जो फिलिस्तीनियों के लिए एक वरदान बन सकती थी, इजराइल के लिए आगे चलकर राहत की सांस लेने वाली बन गई है। इजराइल के अस्तित्व के प्रति ईरान की धमकी भी इस परमाणु सौदे के उपरांत कोई मुद्दा नहीं रह गई है। इसके अलावा, हमास के लिए ईरान का सहयोग राजनीति की बढ़ती हुई पंथवादी प्रकृति के कारण सशर्त ही होगा जो एक ऐसा मुद्दा है जिसके द्वारा फिलीस्तीन के मुद्दे के प्रभावित होने की संभावना है।

फिलीस्तीन एक मुद्दे के रूप में, अधिक दबावकारी मुद्दों के उभरने के कारण क्षेत्र में वास्तविक भू-राजनीति में अपनी प्रधानता खो देगा जो क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व को आंतरिक उथल-पुथल पर ध्यान-केन्द्रित करने के लिए बाध्य करेगा। फिलिस्तीन प्राधिकारी लगभग निरर्थक हो गए हैं तथा वहां शीघ्र ही स्थिति में परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। फिलिस्तीन में नेतृत्व के भीतर विभाजन आने वाले समय में विद्यमान

रहेगा क्योंकि क्षेत्र की अन्य प्राथमिकताएं भी हैं जैसे सीरिया और यमन, जिससे फिलिस्तीन की समस्या स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगी। जितना अधिक फिलिस्तीन का मुद्दा अरब की जनता के राजनीतिक मानस-पटल से अदृश्य होगा, यह इजराइल के लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा और यही स्थिति आज देखी जा रही है। अरब विश्व में विद्यमान संकट और हिंसा इजराइल की ओर से क्षेत्र में समस्त प्रकार के एकलवाद को औचित्यपूर्ण बनाएगी जिससे शांति प्रक्रिया बाधित होगी तथा फिलिस्तीन राज्य का मुद्दा कमजोर बनेगा। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रम्प के आ जाने के बाद इजराइली सरकार प्रत्यक्षत: सुदृढ़ हुई है, जिसमें श्री ट्रम्प में ओबामा के विपरीत एक गहन मित्र और समर्थक पाया है, जिनके अंतिम दिवस नेतनयाहू सरकार के लिए अधिक अनुकूल नहीं रहे थे। व्हाइट हाउस में सत्ता परिवर्तन होने के उपरांत, इजराइल की वेस्ट बैंक में पुनर्गठन नीति को आगे और बल मिलेगा तथा श्री ट्रम्प ने पहले ही यह संकेत दे दिया है कि वे इजराइल में अमेरिकी दूतावास को तेल अवीब से जेरूसलेम में स्थानातंरित करने के लिए अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगे, जिससे अब तक विफल रही शांति प्रक्रिया के और भी खराब होने की संभावना है।

मिश्र : एक समय पर मिश्र को इजराइल के साथ उसके मजबूत सुरक्षा संबंधों, स्वेज नहर की उपस्थिति, जो वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है तथा क्षेत्र में अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार के रूप में क्षेत्रीय राजनीतिक धुरी समझा जाता था। परन्तु हाल के वर्षों में मिश्र के राजनीतिक महत्व तथा राजनीतिक शक्ति में क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति की प्रकृति में हुए तेज परिवर्तनों तथा देश की आंतरिक राजनीति के बदलते हुए आयामों के फलस्वरूप मिश्र के रणनीतिक महत्व और राजनीतिक सुदृढ़ता में भारी गिरावट आई है, जहां इसकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है तथा एक सभ्यात्मक और सांस्कृतिक बल के रूप में इसकी पूर्व छवि भी धूमिल हुई है। मिश्र की आज क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदार अथवा कम-से-कम एक भागीदार अथवा सहयोगकर्ता के रूप में गणना तक नहीं की जाती है तथा ईरान और सउदी अरब के विपरीत, इसके स्वयं के लिए क्षेत्रीय सहयोग जुटाने के कोई नेटवर्क भी नहीं है। निकट भविष्य में, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध वर्गों द्वारा सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र की आवाज़ों का दमन करने की संभावना है तथा प्रमुख आर्थिक प्रगति होने की संभावना भी कम है क्योंकि यह विदेशों द्वारा प्राप्त दान पर आश्रित है। इजराइल के साथ इसके संबंध और भी सुदृढ़ होंगे तथा इससे लोग बड़े पैमाने पर अलग-थलग पड़ जाएंगे तथा तुर्की के साथ संबंध अधिक कड़ुवे होंगे क्योंकि तुर्की की विदेश नीति में निरंतर इस्लाम आडम्बर विद्यमान है तथा मिश्र इस्लाम के साथ निरंतर युद्धरत रहता है।

एक प्रमुख विशेषता, जो भविष्य में मिश्र के परिदृश्य को परिभाषित करेगी, वह विदेशी नीति का संवर्धन करने के लिए घरेलू मुद्दों(मुख्यत: आर्थिक और सुरक्षा)पर इसके द्वारा मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना है। पूर्व में, मिश्र ने एक विशेष दर्जा हासिल किया है क्योंकि यह फिलिस्तीन मुद्दे के साथ अपना सहानुभूतिपूर्ण संबंध रखता था तथा फिलिस्तीनी क्षेत्र में यह एक सक्रिय कार्यवाही करने वाला देश था। परंतु एमबीएच के नेतृत्व वाली सरकार के विरुद्ध विद्रोह के उपरांत, यह प्रतीत हुआ कि इसने फिलिस्तीन का मुद्दा छोड़ दिया और अब यह इजराइल के साथ गहरे संबंध बना रहा है। मिश्र ने क्षेत्रीय मामलों में रुचि लेना बंद कर दिया है तथा एक सक्रिय विदेश नीति वाले देश के रूप में इसकी भूमिका आने वाले वर्षों में समाप्त हो गई प्रतीत होती है।

इस समय यह प्रतीत होता है कि खाड़ी क्षेत्र क्षेत्रीय राजनीति का केन्द्र बन गया है। क्षेत्रीय राजनीति खाड़ी में ही समा गई है। मिश्र फिलिस्तीन के अलावा अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात कहना जारी रखेगा तथा फिलिस्तीन की तुलना में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की इसकी प्राथमिकता इसकी क्षेत्रीय नीति की मुख्य विशेषता होगी। हमास और इजराइल के बीच होने वाली किसी भी आसन्न हिंसा की स्थिति में, इसके द्वारा इजराइल के साथ खड़े रहने की संभावना है क्योंकि इसने सिनई में सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है तथा आतंकवाद के विरुद्ध भी इसका अपना संघर्ष जारी है। इस बात की संभावना भी है कि क्षेत्र में विद्यमान शासन

देश में उनकी लोकप्रियता के खो जाने के कारण आडम्बर के संकेत के रूप में फिलिस्तीन मुद्दे का प्रयोग करें अथवा वे ईरान की बढ़ती आकांक्षाओं का सामना करने के लिए पूरी तरह से इजराइल के साथ मिल सकते हैं।

वित्तीय सहायता के लिए जीसीसी पर इसकी निर्भरता के बने रहने की संभावना है, परंतु यह बात इस पर भी निर्भर करती है कि कितने समय तक मिश्र में शासन जीसीसी की रणनीतिक आवश्यकता के प्रति प्रतिबद्ध बना रह सकता है। परंतु मिश्र वित्तीय सहायता के मुद्दे को अनदेखा नहीं कर सकता है क्योंकि पहले से ही मिश्र की अर्थव्यवस्था संकट में है और इसके फलस्वरूप जनता के क्रोध की एक अन्य लहर उठ सकती है। मिश्र को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जीसीसी की राजनयिक और रणनीतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करना आवश्यक है। मिश्र का रूस के साथ सीरिया पर यूएनएससी में हाल के मतदान, जो सउदी अरब के हितों के अनुरूप नहीं था, ने एक-दूसरे के प्रति रोष उत्पन्न कर दिया है।

यह संभावना है कि मिश्र भविष्य में अन्य राष्ट्रों के साथ भी अपने संबधों को विविधतापूर्ण बनाएगा क्योंकि यह क्षेत्रीय राजनीति में परिवर्तन तथा रणनीतिक संधि की अस्थिर प्रकृति के कारण लंबे समय तक जीसीसी के साथ नहीं चल सकता है। शासन इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है तथा इस संबंध में वैश्विक संधि करने का प्रयास कर रहा है, और जीसीसी की जिहादियों के विरुद्ध पूर्णत: युद्ध का भाग बनने की अपनी सीमाएं हैं। रूस के साथ इसका संबंध इसे मजबूत बनाएगा जिससे यह सउदी अरब की सशर्त रणनीतिक मांगों से दूर अपनी स्वयं की स्वतंत्र सुरक्षा नीति का अनुसरण कर सकेगा(मिश्र ने यमन में पूर्ण युद्ध में भाग नहीं लिया था तथा यह सउदी अरब द्वारा प्रांरभ किए गए इस्लामिक मिलिस्ट्री एलाइंस के प्रति भी उत्साह नहीं रखता था)। रक्षा पर निरंतर मजबूत होते मिश्र-रूस संबंध सउदी अरब के साथ तनाव का एक स्रोत भी है। राष्ट्रपति एल-सिसी रूस और सउदी अरब की प्रतिस्पर्धी मांगों को पूरा करने में परेशानियों का अनुभव करेंगे तथा, संभव है कि वे रूस की सैन्य शक्ति के कारण उसका ही चयन करें।

दोनों के बीच मिश्र की धरती पर प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास उनके संबंधों की गहनता का प्रतीक है। दोनों पक्षों ने 2015 में मिश्र तथा रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार जोन की घोषणा की थी, रूस को स्वेज नहर के समीप औद्योगिक जोन बनाने की अनुमति दी गई और इसके अलावा, रूस ने मिश्र में एक परमाणु संयंत्र का निर्माण करने का वायदा किया तथा दोनों पक्षों ने 3.5 बिलियन यूएस डॉलर के शस्त्र सौदे पर हस्ताक्षर किए।[56] संभवत: मिश्र सतत् सैन्य और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के विरुद्ध एक प्रति-संतुलन के रूप में मास्को का प्रयोग करेगा।

हाल ही में, सीरियाई अधिकारियों के एक उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल के काहिरा दौरे ने सउदी अरब के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर दिया। सीरिया की सरकार द्वारा काहिरा को संयुक्त राष्ट्र और दमस्कस के बीच एलेप्पो को सहायता पहुंचाने हेतु समन्वय के लिए आमंत्रित किया गया था। मिश्र की वित्तीय बाधाओं तथा जीसीसी और आईएमएफ पर उसकी निर्भरता मिश्र को क्षेत्र में रणनीतिक उपाय क्रियान्वित करने की अनुमति नहीं देगी।[57]

मिश्र विभाजित ही बना रहेगा जिसकी सेना के लिए एक उलझी भूमिका है तथा अर्थव्यवस्था निरंतर खराब स्थिति में बनी रहेगी। सेना को क्रांतिकारियों का विरोध करने के रूप में देखा जाएगा तथा समय बीतने के साथ यह अधिक सुदृढ़ होगी। मिश्र में सुरक्षा संकट लोकतांत्रिक संभावनाओं को न्यून बनाएगा तथा यह क्षेत्र में नए गठबंधन भी स्थापित कर सकेगा। मिश्र अधिमानत: यथास्थिति बहाल किए जाने वाले क्षेत्र को देखना पसंद करेगा। अनेक अन्य मुद्दे जैसे अरब रक्षा बल की मांग पूरी नहीं होगी। एकाकी चलना मिश्र के लिए सदैव ही आसान नहीं होगा तथा जब इससे क्षेत्र में अनेक देशों में से किसीएक को चुनने के लिए कहा जाएगा तथा यह

संभवत: कभी-न-कभी उस देश को चुनेगा जो इसे प्रत्यक्षत: प्रभावित नहीं करता है। अमेरिका और ईयू पुन: लोकतंत्र के ऊपर सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे तथा वह देश में लोकतंत्र को चाहने वालो के विरुद्ध प्रति-संतुलन का अतिरिक्त सोत होगा। मिश्र की आर्थिक और सुरक्षा-उन्मुखी विदेश नीति अधिक समय तक बनी नहीं रह सकती है तथा एक बड़ा प्रश्न बना रहता है कि कितने समय तक जीसीसी राष्ट्र मिश्र को समर्थन देंगे और उसे उसकी आर्थिक दिवालिया स्थिति से कब तक बचाते रहेंगे।

तुर्की: जिस प्रकार से राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहे लोकतांत्रिक आकांक्षा रखने वाले राष्ट्रों के लिए तुर्की एक आशा के रूप में उभरा है, किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि क्षेत्र में इसकी भूमिका इतनी जल्द समाप्त हो जाएगी। हाल ही में, विशेषत: राष्ट्रपति एर्डोगन के आगमन के उपरांत, तुर्की इस्लामी और लोकतांत्रिक एकीकरण पश्चिम के लिए एक आदर्श बन गया है तथा अरब उथल-पुथल के तत्काल पश्चात् यह समझा गया था कि लोकतंत्र की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र इस आदर्श का पालन करेंगे। परंतु वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, तुर्की अरब उथल-पुथल का सबसे बड़ा पराजित देश प्रतीत होता है। एक आदर्श के रूप में तुर्की की छवि काफी पहले ही समाप्त हो गई थी तथा इसकी अपनी क्षेत्रीय रणनीतिक उत्तरजीविता भी संकट में आ गई है। इसके 'पड़ोस के साथ शून्य समस्या' के अति-प्रचारित आडम्बर का अनुपालन करने वाला कोई नहीं है। सीरिया के संकट ने एक हितकारी मध्यस्थ के रूप में तुर्की के भ्रम को समाप्त कर दिया तथा इसके 'पड़ोस के साथ शून्य समस्या' की विफलता का संकेत दियाँ[59]।

निकट भविष्य में, क्षेत्रीय मामलों में तुर्की की भूमिका के संकट के प्रति इसके संदेहास्पद दृष्टिकोण के कारण अन्य प्रमख हितधारकों से स्वतंत्र नहीं रही। सीरियाई मामलों का संचालन लगभग रूस-ईरान गठबंधन द्वारा किया गया था। तुर्की के क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने तथा क्षेत्र में इसके साथ स्वयं के मतभेदों के कारण सउदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की संभावना है तथा यह नया समीकरण कुछ समय के लिए निकट भविष्य में अपरिवर्तनीय बना रहेगा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग परिषद का गठन इस तथ्य का संकेत देता है कि दोनों एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग स्थापित करेंगे जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्षत: ईरानी सेना की भूमिका में वृद्धि होगी, पंथवादी राजनीति बढ़ेगी, क्षेत्र में अमेरिका की वापसी होगी तथा अरब क्षेत्रीय प्रणाली विफल होगी और केन्द्रीय प्राधिकारी कमजोर होंगे जो दोनों ही राष्ट्रों के लिए चिंता का स्रोत बन गया है।

आईएसआईएस के विरुद्ध तुर्की का युद्ध संदेहों के घेरे में है क्योंकि सीरिया और ईराक में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्र किसी देश के साथ इसके संबंध नहीं है और इसके आज सीरिया और मिश्र में राजदूत नहीं हैं तथा हाल ही में, इसने इजराइल में अपना राजदूत भेजा है। तुर्की रूपांतरण की प्रक्रिया में शामिल हो सकता था, परंतु हाल में, यह क्षेत्र व्याप्त अस्त-व्यस्तता पर कार्यवाही करते समय अनिर्णयकारी तरीके से कार्य करता हुआ। प्रतीत हुआ क्षेत्र में राज्य-विरोधी कर्ताओं के उदय, कुछ चुनिंदा के प्रति इसकी सहायता, कुर्दो के साथ इसकी अपनी दशकों पुरानी समस्याएं तथा उथल-पुथल के बाद सीरिया के कुर्दो की बढ़ती स्वायत्तता के मुद्दे तुर्की के लिए बहु-आयामी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। उभरते हुए दोषपूर्ण परिदृश्य के प्रति इसके संवेदनशील होने की संभावना है तथा हाल के वर्षों में इराक और सीरिया में कुर्दिश सेनाओं के सुदृढ़ होने के कारण तुर्की पर कुर्द पहले से ही शक्तिशाली हो गए हैं तथा यह आने वाले माहों और वर्षों में तुर्की के लिए एक अन्य बढ़ी सुरक्षा चुनौती प्रस्तुत करेगा।

इसके अपनी सेना को इराकी शासन द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद कुर्दिश पेहेमेर्गा को प्रशिक्षित करने के लिए तैनात करने के पश्चात् इराक के साथ इसके संबंध और अधिक कटु हो गए तथा मोसुल में आईएसआईएस के विरुद्ध वर्तमान युद्ध में, तुर्की उस अभियान में सर्वाधिक नगण्य भागीदार रहा। तुर्की

अरबों और ईरान के मध्य एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था, परंतु सीरिया में उसकी अति-उत्साही नीति ने इसे उस भूमिका से वंचित कर दिया। सीरिया में, इसकी भूमिका एक सहयोगी से एक मध्यस्थ और एक विरोधी की हो गई है। नि:संदेह तुर्की ने रूस के साथ अपने कड़वे संबंधों में पर्याप्त सुधार किया है, परंतु ऐसा अनेक रणनीतिक बलिदान देने के बाद ही किया जा सका है जिससे यह कोई प्रमुख राजनीतिक दाव लगा पाने में समर्थ नहीं है। अपनी ही दहलीज पर, तुर्की को पीछे छोड़ दिया गया है तथा ईरान-रूस-अजरबैजान ने इसके तेल और गैस के विपणन के लिए बाकू में समझौता किया।[59] तुर्की ने सीरिया में आतंकवादी को सहयोग देने के लिए अपयश अर्जित किया तथा यह क्षेत्र में इसकी छवि को निरंतर प्रभावित करना जारी रखेगा। संक्षेप में, तुर्की कम-से-कम प्रभावों के साथ एक शक्ति बना रहेगा तथा अधिकांश क्षेत्रीय देश जैसे ईरान, सउदी अरब और इजराइल ने तुर्की पर से विश्वास खो दिया प्रतीत होता है। संसद द्वारा जनमत संग्रह के लिए संकल्प पारित करने के उपरांत आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता पुन: सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं, जिसके द्वारा पूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी गई है, जो नि:संदेह, राजनीति पर गहरा प्रभाव डालेंगे।

सउदी अरब क्षेत्रीय रूपांतरण के मध्य सउदी अरब की भूमिका और इसके रणनीतिक मार्ग की भावी संभावनाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने से पूर्व यह खंड कतिपय आर्थिक सुधारों पर संक्षिप्त रूप से विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके राजनीति पर पड़ने वाले उन प्रभावों जिनका अवलोकन आज राष्ट्र कर रहा है, पर भी चर्चा की जाएगी। इनका, नि:संदेह ही इसके प्रादेशिक दृष्टिकोण और रणनीतिक दृष्टि पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

राजतंत्रीय शासन ने विगत में अनेक आर्थिक सुधार प्रारंभ किए हैं, विशेष रूप से, मोहम्मद-बिन-सुलेमान को डिप्टी क्राउन प्रिंस की उपाधि दिए जाने औरउनके रक्षा मंत्री बनने के बाद। 2015 में उन्होंने आर्थिक और विकास मामलों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए एक योजना प्रारंभ की तथा एक दो-आयामी योजना (दृष्टि-2030) और (राष्ट्रीय रूपांतरण योजना) क्रमश: अप्रैल और जून, 2016 में प्रारंभ की।[60] उन्होंने यह भी घोषणा की कि सउदी अरब की राष्ट्रीय विकास और आधुनिकीकरण को छोड़कर और कोई विचारधारा नहीं है।[61] यह स्वयं में ही एक प्रमुख परिवर्तन तथा ऐसे देश के लिए अपने अतीत से भिन्न रुख अपनाया था जिसने स्वयं को कभी भी सैद्धांतिक राज्य ही कहाथा जिसे वहाबिस्ट राज्य के रूप में जाना जाता है।

नए आर्थिक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में, शासन के पास देश की अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करने तथा राजस्व के एक पारंपरिक स्रोत के रूप में तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने की एक विस्तृत योजना थी। इसने ऊर्जा पर नए करों की श्रृंखला अधिरोपित करने तथा आर्थिक सहायता में कमी करने की घोषणा कर दी और इसने सरकारी कर्मचारियों के वेतन कोभी 16 प्रतिशत कम कर दिया। पूर्व में इसके कल्याणकारी दृष्टिकोण को छोड़ते हुए स्वास्थ्य देखरेख, बिजली तथा जल क्षेत्र का निजीकरण करने की पहले से ही योजना है। इस नए आर्थिक उद्यम का एक अन्य उद्देश्य इसके नागरिकों को अधिक नौकरियां मुहैया कराना है क्योंकि सउदी जनसांख्यिकी के 70 प्रतिशत भाग पर तीस वर्ष से कम आयु के युवाओं का कब्जा है। ये योजनाएं वार्षिक और मौसमीय तीर्थयात्रियों पर पुराने करों सहित नए करों का अधिरोपण भी शामिल करती हैं। शासन ने पुराने आदर्श-वाक्य 'हम आपको भुगतान करेंगे, और आप चुप रहेंगे'[62] को भी बदल दिया है। परंतु अब यह बात नहीं रह गई है और इसके फलस्वरूप शासन और शासकों के बीच एक नया सामाजिक अनुबंध स्थापित हो गया है, जिसमें यह दावा है कि यदि राज्य हमें भुगतान नहीं करता है, तो हम क्यों चुप रहें। शासन ने विभिन्न राजनीतिक

रिआयतें प्रदान कर दी हैं, जिसमें महिलाओं को परामर्श निकायों (शूरा परिषद) में शामिल किया गया है, उन्हें चुनावी मताधिकार दिया गया है, लोगों को जनता के बीच पीड़ित करने के धार्मिक कार्यकर्ताओं के अधिकारों को कम किया गया है, शूरा को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा आर्थिक मुद्दे सहित अनेक मामलों में राजतंत्र की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

तीर्थयात्रियों पर कर के अधिरोपण द्वारा क्षेत्र में तथा समूचे विश्व में शासन के दर्ज के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तथा इसके शासन की निर्विवाद धर्मशासित ओर निरकुंश प्रवृत्ति पर भी गहरे प्रभाव पड़ने की आशा है। अपने नागरिकों को रोजगार की पेशकश करने का प्रावधान विभिन्न राष्ट्रों जैसे मिश्र, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से श्रमिक बल में स्वाभाविक रूप से कटौती करेगा जिससे मुस्लिम राष्ट्रों के मध्य इसकी रणनीतिक प्रासंगिकता और राजनीतिक स्थिति प्रभावित होगी। अर्थव्यवस्था की इसकी पट्टे पर देने की रीति को समाप्त करने से स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक तुष्टिकरण समाप्त हो जाएगा जिसके फलस्वरूप शासकों और जनता के मध्य नए सामजिक और राजनीतिक संबंध उत्पन्न होंगे। व्यवसथा को लोगों के साथ सामाजिक संपर्क स्थापित करने को पुन: तलाशना होगा तथा, निकट भविष्य में, लोग देश के शासन में अधिक भागीदारी की मांग करने लगेंगे।[63] इसके फलस्वरूप, प्रणाली के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता की एक नई राजनीतिक संस्कृति विकसित होगी क्योंकि विजन 2030 में पहले से ही एक नई प्रशासनिक जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। नए राजवित्तीय नियंत्रण राजनीतिक दमन को जारी रखने की अनुमति नहीं देंगे तथा राजवित्तीय अवपीड़न स्वयं ही साम्राज्य में नए प्रकार का रोष उत्पन्न कर देंगे, जिससे शासन के समक्ष नई चुनौतियां प्रस्तुत हो जाएंगी।[64] नया आर्थिक रूपांतरण और सरकारी निजी क्षेत्रों का नया आमेलन नई लेखापरीक्षा की अपेक्षा करेगा जिससे धार्मिक प्राधिकारियों की स्वायत्तता प्रभावित होगी तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में धार्मिक कुलीन-वर्गों के मध्य मतभेद उजागर होंगे जो आज के शासन की वैधता को निरंतर प्रभावित करना जारी रखेंगे।

राजनीतिक क्षेत्र में नई शुरुआत अधिक व्यापक सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है जहां लोग न केवल अपनी घरेलू नीति को निर्धारित करेंगे, बल्कि भविष्य में देश की विदेश नीति को अभिमुखीकरण प्रदान करने और उसे एक नवीन स्वरूप देने में उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेंगे। सउदी अरब का सुधार किया गया शासन अन्य शासनों की उत्तरजीविता को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि सउदी अरब अन्य जीसीसी प्रणालियों का कटु समर्थक रहा है। यहां यह उल्लेख किया जाता है कि सउदी अरब उस समय कितनी जल्दी बहरीन के बचाव में आ गया था, जब उसे उथल-पुथल के प्रारंभ में क्रांतिकारियों द्वारा चुनौती दी गई थी।[65] सउदी अरब में कोई भी राजनीतिक सुधार अधिक राजनीतिक स्वतंत्रताओं तथा सामाजिक स्वाधीनता की मांगों की तेज लहर को जन्म देगा तथा ऐसा पहले ही बहरीन और ओमान में राजनीतिक सुधारों के लिए निरंतर की जा रही मांगों के रूप में देखा गया है। ओमान में उत्तराधिकार का संकट साम्राज्य में किसी नई लोकतांत्रिक मांग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। देश में प्रारंभ की गई राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वाधीनता के फलस्वरूप इसके रूढिवादी और कट्टरवादी राजनीतिक मॉडल की वैश्विक छवि में परिवर्तन आने की संभावना है।

देश में घरेलू राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की उपर्युक्त संदर्भित प्रकृति के न केवल सउदी अरब में अपितु समूचे क्षेत्र पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक, दोनों ही प्रभाव पड़ने की संभावना है। वर्तमान में, सउदी अरब की क्षेत्र में नीति ईरान-केन्द्रित बनने की संभावना है, जहां तक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता का संबंध है। यह बात उस समय स्पष्ट हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति बनने के पश्चात् अपने प्रथम विदेशी दौरे के लिए सउदी अरब का चयन किया। उन्होंने मई में सउदी अरब की दो-दिवसीय यात्रा की तथा तीन उच्च-स्तरीय शिखर

सम्मेलनों में भाग लिया : सउदी अरब - अमेरिका शिखर-सम्मेलन, जीसीसी-अमेरिका शिखर-सम्मेलन तथा इस्लामिक अरब लीडर्स-यूएस शिखर-सम्मेलन। आर्थिक और रक्षा मामलों के अलावा, क्षेत्र में ईरान के विस्तारवादी डिजाइन पर भी द्विपक्षीय और अमेरिका-जीसीसी शिखर-सम्मेलन में चर्चा की गई। खाड़ी क्षेत्र में ईरान का मुद्दा सामान्य तौर पर जीसीसी नेताओं के लिए और विशेषज्ञ रूप से सउदी अरब के लिए असंतोष और चिंता का प्रमुख और दीर्घकालिक स्रोत है। डोनाल्ड की सउदी अरब की वर्तमान यात्रा की सफलता ईरान को यह सख्त संदेश प्रदान करने पर निर्भर करती है कि अमेरिका खाड़ी सुरक्षा अवसरंचना का एक अभिन्न भाग बना रहेगा। अमेरिकी सेक्रेट्री ऑफ स्टेट श्री टिल्लेरसन ने एक संयुक्त कांफ्रेस में अपने सउदी समकक्षी की उपस्थिति में यह कहा कि डोनाल्ड की खाड़ी राष्ट्रों के दौरे का मुख्य् केन्द्र पड़ोसी ईरान के खतरे को नियंत्रित करना है। खाड़ी शासनों के लिए खाड़ी के देशों के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता से अधिक महत्वपूर्ण बात कोई और हो ही नहीं सकती है। शासक के लिए ग्रह में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के प्रमुख के इस वक्तव्य से अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है कि श्री ट्रम्प ने बल देकर यह कहा कि सउदी अरब का पारंपरिक सैद्धांतिक और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ईरान क्षेत्र में व्याप्त इतनी अस्थिरता के लिए जिम्मेदार है तथा वह आतंकवाद को बढ़ा रहा है।

क्षेत्र में सउदी अरब की संपूर्ण नीति ईरान के प्रभाव को प्रति-संतुलित करना अथवा उसे समाप्त करना है, तथा इसने पहले ही विभिन्न राष्ट्रों जैसे यूके के साथ अपने संबंधों को उन्नयित करना प्रारंभ कर दिया है, जैसाकि पहले वर्णन किया गया है। सउदी अरब का अगला कदम बहरीन का बचाव करना होगा क्योंकि वह इराक और मिश्र को खोने के उपरांत इसे नहीं खोना चाहेगा तथा ऐसा लगता है कि वह यमन को खोने की प्रक्रिया में है। बहरीन के क्षेत्र में प्राक्सियों का अगला केन्द्र बनने की प्रबल संभावना है क्योंकि यह सीरिया और इराक में पराजित हुआ प्रतीत होता है। सउदी अरब अपने रणनीतिक प्रभाव को गहन बनाने तथा ईरानियों और रूसियों की रणनीतिक पैठ के नए स्तर के कारण जीसीसी के भीतर अधिक एकता सृजित करने के लिए जार्डन और मोरक्को को पूर्ण सदस्यता की पेशकश कर सकता है। आने वाले माहों और वर्षों में, जीसीसी और इसके सदस्यों के मध्य विवाद के गहराने की संभावना है, उदाहरण के लिए, कतर और ओमान ईरान के साथ भिन्न-भिन्न संबंध है, जो न केवल शेष जीसीसी से अलग है बल्कि सउदी के नेतृत्व वाले सामूहिक दृष्टिकोण के विपरीत भी हैं।

सउदी अरब हिजबुल्ला में नए शत्रु तलाश सकता है तथा इसके तुर्की के साथ संबंध तुर्की के निरंतर इस्लामिक आडम्बर तथा क्षेत्र में इस्लाम को समर्थन के कारण तनावपूर्ण और अस्थिर बने रहेंगे। सउदी अरब के क्षेत्र में एक प्रधान शक्ति बने रहने की संभावना नहीं है क्योंकि इसका मित्र-राष्ट्र मिश्र अब अधिक प्रधान नहीं रह गया है और पूर्व के विपरीत, इसकी खराब आर्थिक हालत इसे क्षेत्र में इसकी भूमिका का संवर्धित करने अथवा अपने विरोधियों पर विजय हासिल करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगी। क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की सउदी योग्यता का आधार तथा दो पवित्र मस्जिदों की उपस्थिति द्वारा निर्मित इसकी साफ्ट पावर छवि अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी जितनी कभी पूर्व में हुआ करती थी। ईरान के सैन्य और राजनयिक दावे भी सैद्धांतिक और धर्मविज्ञानी इरादों से बेहतर तरह से अनुपूरित होते हैं, जो अनेक देशों को ईरान की ओर आकर्षित करेंगे। हुस्यानी तीर्थयात्रा[66] प्रारंभ किए जाने की खबरें भी मिल रही हैं जो एक नई प्रक्रिया है तथा जिसे इस वर्ष सउदी अरब द्वारा इस वर्ष ईरानियों को हज पर जाने के विरुद्ध एक विकल्प के रूप में आरंभ किया गया है।

अमेरिका की विदेश नीति की शब्दावली में सउदी अरब की एक सौम्य देश तथा इराक और सीरिया की कट्टरवादी देशों के रूप में छवि अब प्रासंगिक नहीं रह गई है। आतंकवाद और आईएसआईएस के विरुद्ध वैश्विक युद्ध तथा सउदी अरब के बदलते और असंगत पक्षों ने इस शासन की छवि को धूमिल किया है तथा उसके

दिखावे और पाखण्ड को उजागर किया है। परमाणु सौदे के कारण ईरान द्वारा पश्चिमी शक्तियों से समझौता करने को सउदी अरब के लिए शून्य परिणाम प्रदान करने वाला माना जा रहा है जिसका अर्थ यह है कि किसी भी धड़े द्वारा दर्शाया गया ईरान-समर्थक पक्ष सउदी अरब के लिए रणनीतिक हानि माना जाएगा। सउदी अरब और उसके सहयोगियों द्वारा अपनाए गए ईरान-विरोधी पक्ष से भी प्रभाव और आह्वान खो देने की संभावना है जो आने वाले वर्षों में सउदी अरब के लिए एक बड़ी रणनीतिक हानि होगी। निष्कर्ष के तौर पर, सउदी अरब क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कारक तो बना रहेगा, परंतु ईरान इस पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा।

समग्र अरब परिदृश्य

समग्र तौर पर, इस क्षेत्र के लिए अस्थिर रहने की संभावना है जो राज्य विरोधी कारकों और शक्ति निर्वात भंगुरता और गहन पंथवाद का केन्द्र बना रहेगा तथा नृजातीय मतभेद राजनीतिक रूपांतरण के मर्म को परिभाषित करेंगे। लीबिया, यमन और सीरिया जैसे राज्य स्थिर होने के लिए एक लंबा समय लेंगे अथवा बहुत अधिक समय तक पृथक-पृथक रहेंगे क्योंकि आज उनके भू-भागों का अधिकांश भाग राज्य-विरोधी कारकों द्वारा अपने अधीन किया गया है। अरब क्षेत्र में बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसांख्यिकी, शहरीकरण, और विद्रोहों द्वारा कारित वर्तमान विवादों के अतिरिक्त आर्थिक सुधार की अनुपस्थिति की चुनौतियों के रूप में संकट के संचयित सेट विद्यमान होंगे।

समस्त राज्यों की नीतियों में सुरक्षा का मुद्दा एक परिभाषित साझी विशेषता होगा तथा इस प्रक्रिया में लोकतंत्र, जो अरब आकांक्षा का प्रमुख अवयव है, मुख्य पीड़ित होगा। निरंतर विवाद क्षेत्र एक लम्बे समय से अपेक्षित आर्थिक एकीकरण को प्रभावित करेगा और पूर्व परियोजनाओं के क्रियान्वयन को बाधित करेगा तथा रोजगार बाजार में शिक्षित व्यक्तियों को समायोजित किया जाना शासनों के लिए एक मुख्य चुनौती होगी। जार्डन और ट्यूनेशिया कौशल शिक्षा के स्तर के कारण बेरोजगारी संकट को प्रबंधित करने में सफल रहे हैं परंतु सउदी अरब और अन्य ऐसा करने में असफल रहे हैं तथा वे अधिशेष योजनाओं पर पूरी तरह निर्भर हैं। आर्थिक एकीकरण की पूर्व योजना क्रियान्वित की गई है जैसे 1997 का ग्रेट अरब फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट (जीएएफटीए) परंतु यह आम बाजार के उस बिंदु तक पहुंचने में विफल रही जिसे 2020 में क्रियान्वित किया जाना था तथा आज यह मृग-मारीचिका प्रतीत होती है।

क्षेत्र का सुरक्षा मुद्दा भी हाल में परिकल्पित आर्थिक सुधारों को प्रभावित करेगा तथा अति आवश्यक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी रोकेगा। उदाहरण के लिएमिश्र मोर्सी के प्रारंभिक दिनों में अनेक आईटी ब्रांडों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, वोडाफोन और आईबीएम को आकर्षित करने में सफल रहा था, परंतु हाल ही में इसने अनेक निवेशकों को खो दिया है।[67] आईकेईएल, जिसने 2017 में मिश्र में अपनी पहली दुकान खोली थी, एक आतंकी हमले के बाद 2015 में देश छोड़ गई तथा कोका कोला ने भी अपना क्षेत्रीय मुख्यालय मिश्र से हटाकर ट्यूनीशिया में कर लिया है, जो इस क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से एकमात्र शांत राष्ट्र है।

अरब विश्व गंभीर आर्थिक संकटों तथा राजनीतिक गुस्से के लिए निकासी (लोकतंत्र पढ़ें) के अभाव में अत:स्फोटित हो सकता है। अरब क्षेत्र भी अनेक मोर्चो पर वापसी करेगा तथा विकास की घड़ीको अनेक दशक पीछे ले जाएगा। 2014 में आईएसआईएस की उपस्थिति ने समस्त क्षेत्र को पूर्णत: अस्त-व्यस्त कर दिया तथा इसके राजनीतिक और आर्थिक कुपरिणाम इसकी समाप्ति पर भी निरंतर विद्यमान रहे क्योंकि वहां ऐसे अनेक संगठन थे जिनके पास उसका स्थान लेने की क्षमता थी। आर्थिक और राजनीतिक सुधार का मुद्दा नेतृत्व के लिए अपील में कोई स्थान नहीं रखता है क्योंकि क्षेत्र ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता की कीमत पर सुरक्षा और आतंक के विरुद्ध युद्ध को पुन: प्राथमिकता प्रदान कर दी है। सेना की राजनीतिक भूमिका में वृद्धि होगी

क्योंकि बढ़ते आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष आसूचना और विशेष कार्य-बल के स्थान पर सशस्त्र सेनाओं द्वारा ही किया जा सकेगा। इन क्षेत्रों में जीसीसी की भूमिका में वृद्धि होगी, तथा यह एक प्रेक्षक से ऊपर उठते हुए क्षेत्रीय नीति-निर्भरता के स्तर तक पहुंचेगा। प्रत्येक राष्ट्र में सुरक्षा बजट में वृद्धि होने की संभावना है जिससे लोगों की सामाजिक सुरक्षा बाधित होगी। कल्याणकारी संसाधन रक्षा सेना की ओर विपथित होंगे क्योंकि खतरा विद्यमान होगा तथा अधिक प्रशंसित सुरक्षा क्षेत्र के सुधार अब कुछ नहीं रह जाएंगे।

अधिकांश राष्ट्र निम्न जीडीपी विकास से पीड़ित होंगे क्योंकि वहां दयनीय सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां विद्यमान हैं। निरंतर चल रहे आर्थिक संकट के फलस्वरूप आर्थिक सहायता का एक बड़ा भाग समाप्त कर दिया जाएगा, जो अधिकांश राष्ट्रों में कल्याणकारी आर्थिक प्रणाली का एक स्तंभ है, जिसके कारण जन आंदोलन छिड़ जाएगा और मिश्र ऐसी स्थिति के लिए सर्वाधिक प्रवण और कमजोर है। राज्य-विरोधी कारक शिया-सुन्नी मतभेदों का अपने हित के लिए प्रयोग करेंगे तथा पंथवाद अधिकांश राज्यों के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करेगा।

राजनीतिक इस्लाम (निर्वाचक, प्राधिकारपूर्ण और क्रांतिकारी) की विभिन्न शाखाओं के भावी क्षेत्रीय राजनीतिक प्रक्रियाओं का भाग बनने की संभावना है तथा वह निष्फल पहलों में भी शामिल होगा। इस्लाम की अनेक शाखाएं हैं तथा एक प्रकार का इस्लाम दूसरों पर अधिरोपित किया जाएगा अथवा उन पर अधिपत्य जमाएगा। सौम्य इस्लामवादी कट्टरवाद की ओर रुख करेंगे तथा यह एक ऐसी शक्ति होगी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उदारवादी पार्टियां विद्यमान राजनीतिक क्षेत्र में उनके लिए कम होते स्थान के कारण कट्टरवाद और इस्लामावाद का कोई अन्य रूप भी अपनाएंगी। पहचान की विभिन्न विशेषताएं भी निर्माण की प्रक्रिया में हैं तथा उनके बीच एक निरंतर अतिव्याप्ति विद्यमान है जैसे धार्मिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पहचानों को पुन: परिभाषित किया जा रहा है।

क्षेत्र में सुरक्षा निर्वात लेबनान से हराक, इराक से लीबिया, लीबिया से सीरिया, सीरिया से मिश्र सिनई, मिश्र सिनई से अल्जीरिया दक्षिण, अल्जीरिया दक्षिण से लीबिया तथा ट्यूनीशिया के पर्वतीय क्षेत्र तक फैल रहा है तथा यह संभावना है कि यह जिहादियों के अवैध नेटवर्क को प्रोत्साहित करेगा और उस प्रकार के नशीले पदार्थों के व्यापार को प्रलोभित करेगा जो आज अफगानिस्तान के मामले में दिखाई देता है। क्षेत्रीय असुरक्षा अन्य राष्ट्रों में भी फैलने की संभावना है तथा यह एक सामूहिक दु:स्वप्न की भांति होगी। पिछले दशक में समाप्त किए जाने के उपरांत पायरेसी के भी लौटने की संभावना है। कुर्दिश मामला, इराक और सीरिया में सुन्नियों का पुनर्वास तथा विकसित होती क्षेत्रीय संरचना में सुन्नियों के भय में कमी आने वाले वर्षों की दीर्घकालिक समस्याएं होंगी।

यह सिद्ध किया जा चुका है कि आईएसआईएस का अभ्युदय शक्ति के निर्वात, सामाजिक और राजनीतिक कुव्यवस्था, तथा अरब अराज्यकता के दृष्टिगत गहरी होती पंथवादी पहचान का संलक्षण है। जहां तक क्षेत्र में आईएसआईएस के भविष्य का संबंध है, यह पर्याप्त रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आंतरिक सुरक्षा मुद्दों और निरंतर व्याप्त राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरताओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। जब तक क्षेत्र में स्थायित्व अथवा कोई मजबूत राजनीतिक संरचना विद्यमान नहीं है, तब तक आईएसआईएस और अन्य जिहादी नेटवर्कों को कमजोर बनाने की आशा भी नहीं की जा सकेगी। एक मजबूत राज्य के अभाव में इसके सामाजिक आधार को समाप्त अथवा सीमित नहीं किया जा सकता है, जो लोगों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करें और उन्हें लाभ पहुंचाएं। यदि राज्य अपने प्रशासन को समुचित रूप से चलाने में विफल रहता है, तो आईएसआईएस के पास समाज में पुन: सिर उठाने तथा एक क्षेत्र में एक समांतर प्रणाली स्थापित करने की पर्याप्त क्षमता मौजूद है। क्षेत्रीय और वैश्विक, दोनों ही शक्तियों को इसकी वैश्वीकृत आपराधिक अर्थव्यवस्था के विकास को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है ताकि इसे सुदृढ़ता प्राप्त करने से रोका जा सके।

नि:संदेह ही, आईएसआईएस ने अपने क्रूर व्यवहार के कारण अपना आडम्बरपूर्ण आकर्षण खो दिया है तथा इसके और भी कमजोर होने की संभावना है तथा इसकी सैद्धांतिक अपील भी उन क्षेत्रों की सीमाओं में विस्तार नहीं कर पाएंगी, जहां राज्य लगभग विफल हो गए हैं। इसके द्वारा अरब क्षेत्र में अनेक उतार-चढ़ाव देखे जाने की संभावना है, तथा इसके पूर्णत: उन्मूलन के लिए अरब विश्व में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के साथ गुंथे एक बहु-आयामी युद्ध की आवश्यकता है।

जहां तक बाहरी शक्तियों की भूमिका का संबंध है, रूस द्वारा अपने मित्र-राष्ट्रों जैसे ईरान और मिश्र के सहयोग से अपने संबंधों और कार्यवाहियों को और गहन बनाए जाने की संभावना है। यदि सीरिया में युद्ध समाप्त भी होता है, तो रूस द्वारा अपनी उपस्थिति में कमी करने की संभावना नहीं है तथा आतंकी नेटवर्क की उपस्थिति वहां पर अपने दीर्घकालिक ठहराव को वैध ठहराएगी। इसके अलावा, पिछले दो दशकों में क्षेत्र में हुए युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस बात की संभावना नहीं है कि रूस अथवा अमेरिका किसी भी समय यह घोषणा करें कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है और अब उन्हें वहां से जाना चाहिए। रूस आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के नाम पर क्षेत्र में बना रहेगा, वैसे ही, जैसे अमेरिका इराक अथवा अफगानिस्तान में जमा हुआ है। सीरिया में रूस की स्पष्ट सफलता भविष्य में भी इसकी रणनीतिक आकांक्षा को गहनता प्रदान करेगी जो अन्य राष्ट्रों जैसे मिश्र को रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करेगा और इसके फलस्वरूप आने वाले वर्षों में रूस पश्चिम एशिया की सुरक्षा और राजनीतिक अवसंरचना का एक प्रमुख अवयव बनकर उभरेगा। क्षेत्र में रूस की दीर्घकालिक उपस्थिति में प्रभाव स्थापित करने की एक नई लड़ाई छेड़ने की क्षमता विद्यमान है जिसमें एक ओर यूरोप और अमेरिका होंगे और दूसरी ओर रूस होगा। ईरान और मिश्र कुछ और समय के लिए क्षेत्र में तुर्की और सउदी अरब के प्रभाव का सामना करने के लिए रूस की उपस्थित बने रहने की मांग करेंगे।

अमेरिका के मोर्चे पर, राष्ट्रपति ट्रम्प ने पहले ही निर्वाचन घोषणा-पत्र पर कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है तथा उनके नए प्रशासन द्वारा लिया गया पहला बड़ा निर्णय सात मुस्लिम-बहुराष्ट्रों (ईरान, इराक, लीबिया, यमन, सूडान, सीरिया और सोमालिया) से अमेरिका में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना था तथा इसके अलावा समूचे विश्व के शरणार्थियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। नीतियों का यह रुख अमेरिका के साथ मुस्लिम विश्व के संबंधों को और भी खराब कर देगा जो पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। श्री ट्रम्प के इस गदम ने अमेरिका की क्षेत्र में अनिच्छुक और संशयी भूमिका के लिए अनेक अरब लोगों को पहले ही नाराज कर दिया है। अनेकों ने यह दावा किया है कि किसी भी प्रतिबंधित राष्ट्र का कोई भी राष्ट्रिक अमेरिकी भू-भाग पर हुए हमले में शामिल नहीं पाया गया है जबकि श्री ट्रम्प ने अनेक राष्ट्रों जैसे सउदी अरब को नजरअंदाज किया है, जिनके राष्ट्रिकों को 9/11 हमले की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। परंतु ट्रम्प की पहली ही विदेश यात्रा के रूप में सउदी अरब की यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले माहों में उनकी राजनीति का मार्गदर्शन किसी अल्पकालिक आडम्बर के स्थान पर रणनीतिक विकल्पों द्वारा अधिक किया जाएगा। इस दौरे ने यह भी संकेत दिया है कि जो लोग अमेरिका की ओर से क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार कीविरक्ति की अपेक्षा कर रहे हैं, वे क्षेत्र में अमेरिकी नीतियों का आकलन करने में गलत हैं।

श्री ट्रम्प ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि क्षेत्र में उनकी नीति आईएसआईएस और इस्लामी आतंकी समूहों के विरुद्ध युद्ध को और भी गहन करना होगा, जिससे अमेरिका की सेना की इस क्षेत्र में आगे और अधिक संलिप्तता की संभावना है। आतंक के विरुद्ध युद्ध से रूस जैसे राष्ट्र अमेरिका के निकट आएंगे और उनके बीच आईएसआईएस एवं अनेक अन्य मुद्दों को लेकर पहले से ही सहमति विद्यमान है। परंतु दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए इस बारे में टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी कि किस प्रकार श्री डोनाल्ड ट्रम आईएसआईएस के विरुद्ध ईरान की अपनी लड़ाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं क्योंकि उनके पूर्व-राष्ट्रपति श्री ओबामा को इस बात से कोई लेना-देना नहीं था कि ईरान आईएसआईएस के

विरुद्ध अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा था कि उनकी प्राथमिकता आईएसआईएस के साथ संघर्ष करना होगा तथा यह वक्तव्य उन्हें सीरियाई सरकार, ईरान और रूस के साथ जोड़ता है[68]। नए प्रशासन के अंतर्गत क्षेत्र की सुरक्षा और आतंकवाद पर अधिक ध्यान दिए जाने से, एक दशक पूर्व राष्ट्रपति बुश के अधीन पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका द्वारा प्रारंभ की गई लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होने की संभावना है जो, अब तक, क्षेत्र में अमेरिकी नीति का एक प्रमुख अवयव रही है।

क्षेत्र में ईयू की भूमिका का मार्गदर्शन पलायन संकट के कारण इसकी सुरक्षा चिंताओं द्वारा किया जाएगा जो संपूर्ण महाद्वीप के लिए एक सौम्य सुरक्षा खतरे के रूप में उभरा है। क्षेत्र में विद्यमान सतत् उथल-पुथल इसके आर्थिक विकास के लिए बाधा होगी तथा क्षेत्र के साथ व्यापार में भी बाधाएं आएंगी यदि स्थिति में सुधार अथवा परिवर्तन नहीं आता है और सुरक्षा स्थापित नहीं की जाती है। क्षेत्र में स्थायित्व ईयू राष्ट्रों के लिए अधिक महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि वे क्षेत्र से प्राप्त होने वाली गैस और तेल पर निर्भर करते हैं, और इसके अलावा रूस के साथ अस्थिर संबंधों को देखते हुए, क्षेत्र को अरब विश्व से और अधिक गैस की आवश्यकता है। ईयू की भूमिका ईरान के परमाणु सौदे को आगे ले जाने में भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वह इस सौदे में एक उत्प्रेरक भागीदार था। इसकी भूमिका अमेरिका और यूके द्वारा जीसीसी देशों के साथ अनेक आर्थिक रक्षा और रणनीतिक सौदों के पश्चात् और भी महत्वपूर्ण बन जाती है।

ईयू के क्षेत्र में आईएसआईएस-विरोधी वैश्विक गठबंधन का अभिन्न भाग बने रहने की संभावना है क्योंकि यह भी महाद्वीप में आतंकवाद के अधिक समय तक खिंचने से समान रूप से पीड़ित हुआ है। इसके अलावा, ईयू की भूमिका विभिन्न राष्ट्रों जैसे लीबिया की आर्थिक प्रक्रिया में अत्यंत सक्रिय और वृहद् होने की भी संभावना है जो इटली का निकटवर्ती पड़ोसी है। इसी प्रकार, फ्रांस में मैक्रोन की विजय के पश्चात् जर्मनी और फ्रांस की भूमिका में भी वृद्धि होगी तथा दोनों ही क्षेत्र में एक नई सुरक्षा संरचना विकसित करने की बात कर रहे हैं।

फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का मुद्दा राष्ट्रपति ओबामा के शासनकाल के विपरीत नए प्रशासन के लिए प्राथमिकता वाला नहीं रह जाएगा, जिन्होंने निरंतर इजराइल के विरुद्ध दबाव डाला था तथा अनेक बार उसकी समाधान की नीति की आलोचना की थी।[69] इजराइल राज्य राष्ट्रपति ट्रम्प के खुले समर्थन से और भी मजबूत होगा जिन्होंने पहले ही कहा है कि वे इजराइल की राजधानी को वर्तमान तेल अवीव से स्थानांतरित कर जेरूसलेम में ले जाने पर कार्य करेंगे।[70] ईरान के साथ परमाणु सौदे के वापस किए जाने की कोई संभावना नहीं है, जैसी कि अनेक लोगों द्वाराकल्पना की गई थी, क्योंकि यह सौदा न केवल ईरान और अमेरिका के बीच है बल्कि इसमें यूरोपीय शक्तियां और संयुक्त राष्ट्र भी शामिल है। इसके अलावा, ईयू परमाणु-संपन्न ईरान युग में अपने व्यापक आर्थिक हितों के कारण सौदे के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देगा। ईरान, रूस और लीबिया के विरुद्ध पश्चिमी कार्रवाइयां पहले ही उन राष्ट्रों के लिए चिंता का प्रमुख विषय बन गई हैं जो बड़े पैमाने पर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए रूस और खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर हैं। परंतु अमेरिका और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और अधिक गिरावट आसकती है तथा ईरान के मिसाइल परीक्षण के विरोध में लगाए गए नए प्रतिबंधों के नवीनतम अधिरोपण ने उनके संबंधों की दिशा को पहले ही निर्धारित कर दिया है, तथा अब समय ही बताएगा कि दोनों प्रतिरोधी किसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। मिश्र पर अमेरिका के रुख में कोई बड़ा परिवर्तन होने की आशा नहीं है तथा मिश्र क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख मित्र-राष्ट्र अर्थात् इजराइल के हित के लिए

कार्य करना जारी रखेगा। जहां तक जीसीसी राष्ट्रों के प्रति अमेरिका की नीति का संबंध है, यह संभावना है कि नए राष्ट्रपति यथास्थिति को बहाल रखेंगे क्योंकि कोई भी नया प्रयोग क्षेत्र में पुराने मुद्दों को भड़का सकता है जो पहले ही अनेक संकटों से ग्रस्त चल रहा है।

निष्कर्ष

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि निकट भविष्य में भी यह क्षेत्र अस्त-व्यस्तता के दौर में ही रहेगा। जैसीकि अनेक लोगों द्वारा कल्पना की जा रही है कि उथल-पुथल के बारे में जानकारी केवल पंथवादी अथवा नृजातीय धड़ों द्वारा ही नहीं दी जाएगी, बल्कि अन्य कारक भी धीरे-धीरे उत्पन्न होंगे जो क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास की वंशावली में समाहित होंगे तथा जो क्षेत्रीय राज्य प्रणाली और सुरक्षा अवसंरचना को कमजोर बनाने में समान रूप से उत्प्रेरक होंगे जिसका वैश्विक सुरक्षा पर गहन प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती हुई जटिलता और उसके उपरांत मूर्त एवं अमूर्त कारकों का परस्पर जुड़ाव क्षेत्रीय राजनीति की एक मुख्य विशेषता होगी। इस समय जो बात सबसे अधिक चिंताजनक है, वह शीघ्र ही किसी समाधान पर पहुंचने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक पहलों के संबंध में क्षेत्र में संबंधित नेताओं और विद्रोही बलों की ओर से सहयोग का अभाव होना है। किसी एक देश में परिवर्तन संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करेगा। भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक विवाद के गहन होने से सामूहिक संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा तथा क्षेत्र में शक्ति संरचना का उदय होगा।

इसमें संदेह नहीं कि अरब उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में लोग भी उत्प्रेरक बलों के रूप में उभरे हैं, परंतु कमजोर राष्ट्रों के साथ इनकी संलिप्तता तथा राज्य-विरोधी तत्वों के प्रसार ने लोगों के जोश को अर्थहीन बना दिया है, इसके स्थान पर, उनकी राजनीतिक ऊर्जा विवाद का विरोध करने अथवा विवाद का उपशमन करने की ओर विपथित हो रही है जिसका कोई राजनीतिक परिणाम नहीं निकल रहा है। ईरान, सउदी अरब, तुर्की और मिश्र के मध्य प्रतिद्वंद्विता क्षेत्र के भविष्य का निर्माण करेगी। राष्ट्रपति ट्रम्प की सउदी अरब की यात्रा तथा ईरान के विरुद्ध उसके रणनीतिक युद्ध के साथ खुली भागीदारी की उनकी घोषणा के पश्चात् यह बात और अधिक स्पष्ट हो गई है जिसने सउदी अरब को और भी अधिक मजबूत बनाया है। आगामी समय में यह देश इराक के अपने नुकसान तथा सीरिया और यमन में कमजोर होती स्थिति की प्रतिपूर्ति ईरान के विरुद्ध एक दृढ़ पक्ष प्रस्तुत करते हुए करेगा। परंतु अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यह बात कितनी प्रभावी होगी और यह रणनीतिक और राजनीतिक संदर्भ में सउदी अरब से कितना लाभान्वित होगा।

दूसरी ओर, ईरान शक्ति के शिखर पर पहुंच जाएगा तथा क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों को नियंत्रित करेगा, परंतु यह इस बात पर निर्भर होगा कि राष्ट्रपति रूहानी के दूसरे कार्यकाल के दौरान ईरान की आंतरिक राजनीति किस प्रकार संचालित की जाती है। तथापि, ईरान जून, 2017 में रियाद शिखर-सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रम्प की नीतिगत घोषणा को ध्यान में रखते हुए ईरान कठिन परिस्थितियों का सामना भी कर सकता है जहां उन्होंने जीसीसी भागीदारों से क्षेत्र में ईरान के इरादों का विरोध करने का आह्वान किया था। क्षेत्र द्वारा नई राजनीतिक, सामाजिक, सैद्धांतिक और रणनीतिक सत्यताओं का सामना किए जाने की संभावना है तथा क्षेत्र की व्यवस्था का निर्धारण करने वाली अनेक प्रमुख रणनीतिक प्रवृत्तियां तैयार हो रही हैं, तथा यह व्यवस्था इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि कुछ राज्य शक्तिशाली हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें से कुछ कमजोर हो गए हैं। यह संभावना कम है कि इजराइल स्वयं को विकसित होते राजनीतिक परिदृश्य में बेहतर ढंग से ढाल ले, जब तक कि वह अपनी सुरक्षा को मिलने वाली प्रमुख चुनौती से निपट न ले, क्योंकि इजराइल का मूल उद्देश्य, सुरक्षा विद्यमान रणनीतिक और राजनीतिक योजना में ही पूर्ण हो सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इजराइल सर्वाधिक विशाल लाभार्थी है तथा वह क्षेत्र में विद्यमान वर्तमान अनिश्चितता में तब तक शामिल होना नहीं चाहेगा, जब तक कोई प्रमुख रणनीतिक परिवर्तन घटित न होता हो।

इस प्रक्रिया में सबसे अधिक हानि में जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाएं रहेंगी जिन्होंने लाखों लोगों को कई सप्ताहों के लिए क्षेत्र के विभिन्न भागों में एकत्र किया है। अरब उथल-पुथल के तत्काल उपरांत, लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षा समूचे क्षेत्र में व्याप्त सतत् पंथवादी, जनजातीय और क्षेत्रीय विभाजनों में खोकर रह गई। उदाहरण के लिए मिश्र सेना को पूर्ण नियंत्रण में रख रहा है तथा सेना को कोई आसन्न संकट नहीं है। इसके अलावा, मानवाधिकार मुद्दे पर कोई वैश्विक शोर-शराबा नहीं मच रहा है तथा राजनीतिक प्रतिपक्ष लगभग समाप्त हो गया है। मुख्यधारा का मीडिया पर आतंकवाद और सुरक्षा का मुद्दा छाया हुआ है तथा लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

इसमें संदेह नहीं कि अरब ने राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करने का एक बड़ा अवसर गवां दिया है तथा वर्तमान विध्वंसक स्थिति के लिए दोष निर्धारित करना भी बहुत कठिन है। परंतु मिश्र और जीसीसी राष्ट्रों में अनेक लोग इस तथ्य से प्रसन्न है कि उनके शासकों ने उन्हें सीरिया और लीबिया जैसी स्थिति से बचा लिया जहां लाखों लोग विस्थापित हो गए थे और हजारों मारे गए थे।

अंत में, अरब उथल-पुथल के बाद की राजनीति ने अरब एकता की पारंपरिक परिकल्पना को गलत सिद्ध किया है और यह क्षेत्र एक बार फिर राजनीतिक, बौद्धिक, भावनात्मक और रणनीतिक दृष्टि से टूट गया प्रतीत होता है। इस दौरान, अरब उथल-पुथल तथा तत्पश्चात् हुए राजनीतिक विकास ने कुछ लोगों के इस दावे को सिद्ध कर दिया है कि एक सजातीय सत्ता और एकीकृत राजनीतिक बल के रूप में अरब विश्व का दावा खोखला है। यह भ्रम और नारेबाजी के मिश्रण के अलावा और कुछ नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र एक नया रास्ता ढूंढता प्रतीत होता है जिसके लिए वह अपनी राष्ट्रीय राजनीतिक और रणनीतिक आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त करता है।

****

पादटिप्पणियां:

[1]फ्लोरेंस गॉब और एलेक्जेंडर लबान(संपा.) अरब फ्यूचर्स : थ्री सिनारियोज फॉर 2025, यूरोपीय संघ सुरक्षा अध्ययन संस्थान, रिपोर्ट सं. 22, 22 फरवरी 2015). http://www.iss.europa.eu/uploads/ media/Report_22_Arab_futures.pdf, (26 अक्तूबर 2016 को एक्सेस किया गया)।

[2]मार्वात हतेम, मिश्र में 3 जुलाई के सैन्य विद्रोह पर वाद-विवाद : यह विद्रोह की परिभाषा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण विषय के बारे में है, सेंटर फॉर मेलेमोस्ट स्टडियर, 3 नवम्बर, 2013 http://static.sdu. dk/mediafiles/3/7/B/%7B37BCEEAA-C02D-4EA0-94DC- 3C3F70F67C35%7DMH1113.pdf, (28 जनवरी, 2016 को एक्सेस किया गया)

[3]डेविड हेल्ड एवं क्रिश्चियन कोटेस अलरिक्सेन, 'दि अरब स्प्रिंग एंड दि चैंजिंग बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर्स, ओपन डेमोक्रेस, 26 फरवरी, 2014 https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/david-held- kristian-coates-ulrichsen/arab-spring-and-changing-balance-of-global- power (16 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[4] डेविड हेल्ड एवं क्रिश्चियन कोटेस अलरिक्सेन, 'दि अरब स्प्रिंग एंड दि चैंजिंग बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर्स, ओपन डेमोक्रेसी, 26 फरवरी, 2014 https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/david-held- kristian-coates-ulrichsen/arab-spring-and-changing-balance-of-global- power (16 नवम्बर जनवरी, 2016 को एक्सेस किया गया)

[5]सउदी अरब सीरिया विरोधी लड़ाकों को वेतन का भुगतान करेगा, अल-अरेबिया न्यूज़, 23 जून, 2012 http://english.alarabiya.net/ articles/2012/06/23/222214.html, on (20 जनवरी, 2017 को एक्सेस किया गया)

[6]जाकी सामी एलावाकी, 'दि जियोस्ट्रेटेजिक कंसीक्वेंसेस ऑफ दि अरब स्प्रिंग', ओपन डेमोक्रेसी, 22 नवम्बर, 2014 https:// www.opendemocracy.net/arab-awakening/zaki-samy-elakawi/geostrategic-consequences-of-arab-spring, (13 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)।

[7] मीना सिंह रॉय (संपा.) एमेर्जिंग ट्रेंड्स इन वेस्ट एशिया : रीजनल एंड ग्लोबल इंप्लीकेशंस, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, बहुवागन प्रेस, 2014)।

[8] तदेव

[9] सीरियन कंफ्लिक्ट : फोर यीअर्स ऑन, स्टेफने डी. मिस्तूरा, सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत, दि चातम हाउस, दि रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, 5 मार्च, 2015 https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/ field/field_document/20150305TheSyrianConf lict.pdf, (22 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)।

[10]डा. क्लेरे स्पेंसर, 'दि फार्गोटन सीरिया, ' दि चातम हाउस, 4 अक्तूबर, 2013 https://www.chathamhouse.org/media/comment/ view/194629, (22 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)।

[11] फ्लोरेंस गॉब और एलेक्जेंडर लाबान(संपा.), अरब फ्यूचर्स : थ्री सिनारियोज फॉर 2026, ओपी. सीआईटी.

[12] जाकी सामी एलावाकी, 'दि जियोस्ट्रेटेजिक कंसीक्वेंसेस ऑफ दि अरब स्प्रिंग', ओपन डेमोक्रेसी, 22 नवम्बर, 2014 https:// www.opendemocracy.net/arab-awakening/zaki-samy-elakawi/geostrategic-consequences-of-arab-spring, (13 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)।

[13]माइकल आर गोर्डन, 'मेडलिंग नेबर्स, अंडरकट इराकी स्टेबिलिटी, 'न्यूयार्क टाइम्स' 5 दिसम्बर, 2010. http://www. nytimes.com/2010/12/06/world/middleeast/06wikileaks-iraq. html?pagewanted=all, (10 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)।

[14]एफ-ग्रेगरी गॉज III, 'बियांड सेक्ट रियनिज्म : दि न्यू मिडल ईस्ट कोल्ड वार', ब्रूकिंग दोहा सेंटर, 11 जुलाई, 2014. https:// www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/English-PDF-1.pdf, (20 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)।

[15]जब मुस्लिम विश्व में शिया-सुन्नी मतभेद की बात आती है, तो तीन राष्ट्र पाकिस्तान, सउदी अरब और तुर्की सदैव ही एक प्रमुख सुन्नी धड़े के रूप में साथ खड़े होते हैं।

[16] एफ. गैरेगरी गौस, बियांड सेक्टेरियन : दि न्यू मिडल ईस्ट कोल्डवार, ब्रूकिंग्स, https://www.brookings.edu/events/beyond- sectarianism-the-new-middle-east-cold-war/ (6 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[17] पॉल डानाहर, दि न्यू मिडल ईस्ट : दि वर्ल्ड ऑफ्टर दि अरब स्प्रिंग, लंदन : ब्लूम्सबेरी पब्लिशिंग, 2013, पृष्ठ 376, 377.

[18]किटीना कॉश, 'जियोपालिटिक्स एंड डेमोक्रेसी इन मिडल ईस्ट (संपा.), एफआरआईडीई, 2015 http://fride.org/download/ Geopolitics_and_Democracy_in_the_Middle_East.pdf, (28 अक्तूबर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[19]किटीना कॉश, 'जियोपालिटिक्स एंड डेमोक्रेसी इन मिडल ईस्ट (संपा.), एफआरआईडीई, 2015 http://fride.org/download/Geopolitics_and_Democracy_in_the_Middle_East.pdf, (28 अक्तूबर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[20]तदेव

[21] नईल शमा, इजिप्टियन फॉरने पॉलिसी फ्रॉम मुबारक टु मोर्सी : अंगेस्ट दि नेशनल इंट्रेस्ट, लंदन : रूटलेज, 2014, पृ. 216.

[22] एफ. ग्रेगरी गॉस III 'सउदी अरेबिया इन दि न्यू मिडल ईस्ट, काउंसिल स्पेशल रिपोर्ट, http://www.cfr.org/saudi-arabia/ saudi-arabia-new-middle-east/p26663 (20 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[23] डेनियल बार-ताल और डिल्का एंटाबी, "सीज मेंटेलिटी इन इजराइल, "तेल अवीव विश्वविद्यालय, http://www.psych.lse.ac.uk/psr/PSR1992/1_1992BarTa. pdf, (19 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[24] प्रधानमंत्री नेतनयाहू द्वारा टिप्पणियां, कैबिनेट कमनीक, http:// mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2011/Pages/Cabinet_communique_16-Jan-2011.aspx, (20 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[25] क्रिस्टीना कॉश, मध्य पूर्व में भू-राजनीति और लोकतंत्र (संपा.) ओपी. सीआईटी.

[26]एनाटोल लीवेन, "पुतिन शोज हिज रीयलिज्म इन सीरिया" अल जजीरा, 16 अक्तूबर, 2015, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/10/putin-shows-realism-syria-151013102705917.html, (27 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[27]अबुल जलील अल-मोरहोन, "दि स्टोरी ऑफ रशिया-सीरिया रिलेशंस" मिडल ईस्ट मॉनीटर, 7 फरवरी, 2014. https://www.middleeastmonitor.com/ articles/europe/9631-the-story-of-syrian-russian-relations, (25 जनवरी, 2015 को एक्सेस किया गया)

[28] जोन बी. एलटेरमैन एवं कैरोलिन बर्नेट , *तुर्की, रसिया एंड ईरान इन थे मिडिल ईस्ट, रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र, नवम्बर* , 2013. https://www.csis.org/analysis/turkey-russia-iran- nexus (25 जनवरी, 2017 को एक्सेस किया गया)

[29] यान, "सीरिया एलाइज़ : व्हाई रशिया, ईरान एंड चाइना, ओपी.सीआईटी.

[30]अहमद रशीद मलिक, 'जैपनीज़ रिस्पांस टु क्राइसिस इन सीरिया,' पाकिस्तान टुडे, 13 फरवरी, 2013, http://www.pakistantoday. com.pk/2013/09/13/japans-response-to-crisis-in-syria/, (02 फरवरी, 2017 को एक्सेस किया गया)

[31]योराम एवरॉन, 'चाइना-जापान इंटरेक्शंस इन दि मिडिल ईस्ट : ए बैटल ग्राउंड ऑफ जापांस रीमिटेराइजेशन, 'दि पैसेफिक रिव्यू, खंड 30 (2017), अंक 02 http://www.tandfonline.com/eprint/ YAFsG9SIe6xHPnk9TJwU/full, (02 जनवरी, 2017 को एक्सेस किया गया)

[32]डा. योकिको मियागी, 'जापान एंड दि मिडल आफ्टर दि अरब स्प्रिंग, आईडीई एमई समीक्षा, खंड I (फरवरी, 2014) http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Me_review/pdf/201402_02.pdf, (30 जनवरी,2017 को एक्सेस किया गया)

[33]डा. योकिको मियागी, 'जापान एंड दि मिडल आफ्टर दि अरब स्प्रिंग, आईडीई एमई समीक्षा, खंड I (फरवरी, 2014) http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Me_review/pdf/201402_02.pdf, (30 जनवरी,2017 को एक्सेस किया गया)

[34]अहमद रशीद मलिक, 'जैपनीज रिस्पांस टु क्राइसिस इन सीरिया', ओपी. सीआईटी.

[35]योरम एवरॉन, 'चाइना जापान इंटरेक्श इन दि मिडल ईस्ट : ए बैटल ग्राउंड ऑफ जापान्स रीमिलिटराइजेशन, ओपी सीआईटी

[36]जापान का विदेश मंत्रालय http://www.mofa.go.jp/region/ page6e_000028.html (5 जुलाई, 2016 को एक्सेस किया गया)

[37]योरम एवरॉन, 'चाइना जापान इंटरेक्श इन दि मिडल ईस्ट : ए बैटल ग्राउंड ऑफ जापान्स रीमिलिटराइजेशन, ओपी सीआईटी

[38] मीना सिंह रॉय (संपा.), एमेर्जिंग ट्रेंड्स इन वेस्ट एशिया : रीजनल और ग्लोबल इंप्लीकेशन,' ओपी - सीआईटी।

[39]"सीरिया वार : यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल वीटोज ऑन ऐलेप्पो" एल-जजीरा http://www.aljazeera.com/news/2016/10/syria-war-security-council- votes-aleppo-161008164635062.html, (3 फरवरी, 2017 को एक्सेस किया गया)

[40]दि गार्जियन, http://www.theguardian.com/politics/2011/oct/02/ david-cameron-libyan-war-analysis, (26 दिसम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[41]लीबिया : कैमरून एंड सर्कोजी मॉब्ड इन बेंगाजी, बीबीसी न्यूज, http://www.bbc.com/news/world-africa-14934352, (20 जनवरी, 2016 को एक्सेस किया गया)

[42]यमन पर संयुक्त वक्तव्य, विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय, 16 अक्तूबर, 2016https://www.gov.uk/government/news/joint- statement-on-yemen--3, (फरवरी, 2017 को एक्सेस किया गया)

[43]मीना सिंह राय(संपा.) एमर्जिंग ट्रेंड्स इन वेस्ट एशिया : रीजनल एंड ग्लोबल इंप्लीकेशन, ओपी - सीआईटी

[44]टॉम के इंगटन, 'इटली रिपोर्टेडली सेंड्स इट्स स्पेशल फोर्स इन लीबिया, डिफेंस न्यूज, 11 अगस्त, 2016 http://www.defensenews.com/story/ defense/international/mideast-africa/2016/08/11/libya-italy-special- forces-isis/88567660/, (3 फरवरी, 2017 को एक्सेस किया गया)।

[45]माजेक मंदोर, इंजिप्ट शिफ्ट फ्रॉम सउदी अरेबिया टु रशिया, कार्नेजी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, 03 नवम्बर, 2016, http:// carnegieendowment.org/sada/65030, (20 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[46] तदेव

[47]एलिसा मिलर, "अंडर स्टैंडिंग रीसेंट इजिप्ट सउदी टेंशन", एटलांटिक काउंसिल, 25 अक्तूबर, 2016, http://www.atlanticcouncil. org/blogs/menasource/understanding-recent-egypt-saudi-tensions#. WBC8PkJ54xs.facebook, (29 अक्तूबर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[48]कटर्की सेज़ इट्स ट्रूप टु स्टे इन इराक अनटिल इस्लामिक स्टेट इज क्लीयर्ड फ्रॉम मोसुल, रायटर, 13 अक्तूबर, 2016. http://www.reuters.com/ article/us-mideast-crisis-iraq-turkey-idUSKCN12C0KF?il=0, (22 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[49]नेसन रफानी, 'ईरान एंड दि अरब स्प्रिंग : http://www.lse.ac.uk/ IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL_LSE_IDEAS__ IranAndArabSpring_Rafati.pdf (20 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[50] यानिव वोलेर, 'टर्मोइल एंड दि अनसेर्टेनिटी : इजराइल एंड दि न्यूमिडल ईस्ट http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/ pdf/SR011/FINAL_LSE_IDEAS__IsraelAndTheNewMiddleEast_ Voller.pdf, (13 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[51]डेविड हार्ट्ज 'सउदी अरेबिया रीप्स व्हाट इन हास सोड्' 02 नवम्बर, 2016, मिडल ईस्ट आई, http://www.middleeasteye.net/columns/ saudi-foreign-policy-1215866329 (05 फरवरी, 2017 को एक्सेस किया गया)

[52]http://fride.org/download/PB202_Iran_in_the_Middle_East.pdf, (05 फरवरी, 2017 को एक्सेस किया गया)

[53] गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल को दिया गया प्रधानमंत्री का भाषण, 2 दिसम्बर, 2016, गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल, मनामा https://www.gov. uk/government/speeches/prime-ministers-speech-to-the-gulf-co- operation-council-2016, (10 दिसम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)।

[54] http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=120061, (5 फरवरी, 2016 को एक्सेस किया गया)

[55] नेतनयाहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण, http://www.jpost.com/ Israel-News/Benjamin-Netanyahu/READ-Full-text-of-Netanyahus-speech-to-UN-General-Assembly-468500, (2 नवबर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[56] http://fride.org/download/Geopolitics_and_Democracy_in_the_ Middle_East.pdf, op. cit.

[57] डेविड हेल्ड और क्रिश्चन कोटेस अलरिचसन, 'दि अरब स्प्रिंग एंड दि चैंजिंग बैलेंस ऑफ पावर", ओपन डेमोक्रेसी, 26 फरवरी, 2014. https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/david- held-kristian-coates-ulrichsen/arab-spring-and-changing-balance-of- global-power, (16 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[58] एर्जेस्बेट एन. रोज्सा, "जियो स्ट्रेटेजिक कंसेक्वेंसेस ऑफ दि अरब स्प्रिंग", 19 पत्र आईईमेड, यूरो मेसो के साथ संयुक्त श्रृंखला जून, 2013. www.files.ethz.ch/isn/182508/Paper_EuroMeSCo19.pdf, (16 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)

[59] न्यूज अपडेट, बीबीसी मॉनीटरिंग, 4 अक्तूबर, 2016 https://monitoring. bbc.co.uk/#/product/c1d8emge, (15 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)।

[60]बर्नार्ड हेकेल, 'केन सउदी अरेबिया रिफार्म इटसेल्फ, मिंट, 30 दिसम्बर, 2016 http://www.livemint.com/Opinion/lZiG2pp GPQAfhGbzfM1nWO/Bernard-Haykel--Can-Saudi-Arabia-reform- itself.html, (01 फरवरी, 2017 को एक्सेस किया गया)

[61]डेनिस रॉस, 'इज़ सउदी अरेबिया ए रेवोलूशनरी डिसगाइस्ड एज रिफार्म, वाशिंगटन पोस्ट, 18 सितम्बर, 2016, https://www.washingtonpost. com/opinions/global-opinions/in-saudi-arabia-a-revolution- disguised-as-reform/2016/09/08/979f03f6-7526-11e6-b786- 19d0cb1ed06c_story.html, (05 फरवरी, 2017 को एक्सेस किया गया)

[62] डेविड हेल्ड एवं क्रिश्चन कोटेस अलरिचसेन, 'दि अरब स्प्रिंग एंड दि चैंजिंग बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर्स', ओपी. सीआईटी.

[63] बनार्ड हेकेल, 'कैन सउदी अरेबिया रिफार्म इटसेल्फ, ओपी सीआईटी

[64]http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/ economic-reform-saudi-arabia-middle-east-security-20301/, (20 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)।

[65]http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/ economic-reform-saudi-arabia-middle-east-security-20301/, (20 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया)।

[66] इस वर्ष ईरान में मनाए जाने वाले सामूहिक मातम में, जो हुसैन की मृत्यु पर शोक मनाने का अवसर होता है, ईरान के कुछ उदारवादी समाचार पत्रों ने इसी सामूहिक मातम को हज हुसैनी का नाम दिया, जो शिया धर्म मेंएक नवीन विचार है क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से हज केवल मक्का के पवित्र शहर में यात्रा करके ही पूर्ण किया जाता है।

[67] फ्लोरेंस गॉब और एलेक्जेंडर लाबान (संपा.), अरब फीचर्स : थ्री सिनारियोज फॉर 2025, ओपी – सीआईटी

[68]http://www.alternet.org/election-2016/donald-trumps-middle-east- policy-disaster, (5 फरवरी, 2017 को एक्सेस किया गया)

/1040405, (20 नवम्बर, 2016 को एक्सेस किया गया

[70] तदेव